घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 262- गुरूवार 23- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

नीट धांधली और पेपर लीक पर संसद में हंगामा...राहुल समेत कांग्रेस सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे

राज्यसभा में खड़गे बोले...प्रधान इस्तीफा दें,फिर चर्चा करेंगे

नई दिल्ली,22 जुलाई 2026। संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को विपक्ष ने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के बीच लोकसभा-राज्यसभा को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि, वे सदन में नीट पेपर लीक मामले में चर्चा तभी चाहते हैं जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। सदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि सरकार पिछले तीन दिनों से लगातार हृश्वश्वञ्ज पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की पेशकश कर रही है। लेकिन विपक्ष मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। विपक्षी पार्टियां 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, पेपर लीक का विरोध कर रही हैं।

राजनाथ बोले...विपक्ष युवाओं को राजनीतिक हथियार न बनाएं...

राजनाथ सिंह ने कहा...दिल्ली में जारी विरोध-प्रदर्शन गंभीर चिंता का विषय हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और युवाओं को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है।मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक,परिपक्व और विवेकशील युवा ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली-भांति समझते हैं और वे प्रगति,विकास तथा राष्ट्रनिर्माण के मार्ग को ही चुनेंगे।

खड़गे बोले...पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें फिर चर्चा होगी...

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा...शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दें फिर सदन में चर्चा होगी। पीएम मोदी पहले इस बात का आश्वासन दें। दरअसल सरकार सदन में नीट पेपर लीक मामले में चर्चा को तैयार है।

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी मानसून सत्र से सस्पेंड किए गए...

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को पूरे मानसून सत्र से निलंबित कर दिया गया है। कल्याण के खिलाफ यह कार्रवाई महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर की गई थी। दरअसल मई 2026 में तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तिदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कल्याण बनर्जी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी।

राज्यसभा में जेपी नड्डा बोले...संसदीय मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर-जिम्मेदाराना है। हम संसद में उनके इस लोकतंत्र-विरोधी व्यवहार को साफ देख सकते हैं। संसदीय मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अभी-अभी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

वेणुगोपाल बोले...शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें; रिजिजू बोले...सरकार चर्चा को तैयार : लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष की मांग साफ है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार पिछले तीन दिनों से लगातार कह रही है कि वह नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार नियमों के तहत सार्थक चर्चा चाहती है, ताकि देश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बात हो सके। गांधी परिवार देशविरोधी तत्वों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है।

अखिलेश बोले...बेटियों के कपड़े फाड़े,ये अधिकार किसने दिया...

संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को विपक्ष ने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में पूछा कि पुलिस को बेटियों के कपड़े फाड़ने का अधिकार किसने दिया? लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष की मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार पिछले तीन दिनों से लगातार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की पेशकश कर रही है।

सीजेपी का नड्डा के आवास पर जाने से इनकार, जंतर-मंतर के पास तटस्थ स्थान पर वार्ता का दिया प्रस्ताव

सोशल मीडिया अभियान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर जाकर बातचीत करने से इनकार किया है। सीजेपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बातचीत जंतर-मंतर पर अथवा इसके निकट किसी तटस्थ स्थान पर होनी चाहिए। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि आज सुबह पुलिस ने सीजेपी प्रतिनिधियों से संपर्क कर जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्री नड्डा उनसे बातचीत करना चाहते हैं और इसके लिए अपने आवास पर आने का निमंत्रण दिया है, लेकिन सीजेपी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सौरभ दास ने कहा कि सीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि किसी मंत्री के घर या कार्यालय नहीं जाएगा। जंतर-मंतर पर जनता दरबार लगा हुआ है और यदि सरकार बातचीत करना चाहती है तो मंत्रियों को जनता के बीच आना चाहिए। उन्होंने कहा कि वार्ता जंतर-मंतर पर ही होनी चाहिए। यदि सुरक्षा कारणों से मंत्री जंतर-मंतर आने में असमर्थ हैं, तो सीजेपी प्रदर्शन स्थल के पास किसी तटस्थ स्थान पर बातचीत के लिए तैयार है।

जंतर-मंतर पर पुलिस और छात्रों में झड़प

सीजेपी समर्थकों ने पत्थरबाजी की पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे

नई दिल्ली,22 जुलाई 2026। दिल्ली के जंतर-मंतर पर बुधवार रात छात्रों और पुलिस में झड़प हो गई। सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। घटना से जुड़े कुछ वीडियो सामने आए। जिसमें प्रदर्शनकारियों के हाथ में भी लाठी दिख रही है। वो पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले 20 जुलाई को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान झड़प हुई थी। प्रदर्शनकारी संसद गेट के करीब पहुंच गए थे। उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया था।

प्रदर्शन के बड़े अपडेट्स...

- अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश को उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा।
- केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली में तैनात करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर करीब 2000 जवानों को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एयरलिफ्ट कर लाया गया।
- दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के कारण 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। हालांकि शाम को सभी स्टेशन खोल दिए गए।
- दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान आरएएफ के एक जवान पर हमले के मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक, वायरल वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी आरएएफ जवान के साथ मारपीट करते, आरएएफ के वाहन पर पथराव करते और उसमें तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं।

नीट को हमेशा के लिए खत्म करो... थलपति विजय की पार्टी ने कर दी बड़ी मांग

चेन्नई,22 जुलाई 2026। नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय भी छात्रों के समर्थन में खुलकर मैदान में आ गए हैं। तमिल सिनेमा के 'थलपति' और अब सूबे के मुखिया विजय की पार्टी तमिझगा वेत्री कज़गम ने नीट परीक्षा को लेकर एक ऐसी मांग कर दी है, जिसने सियासी पारे को और भी ज्यादा चढ़ा दिया है। टीवीके ने दो टूक कहा है कि नीट में धांधली रोकना ही काफी नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रवेश परीक्षा को ही हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देना चाहिए।

संविधान में बड़े बदलाव की उठी मांग

छात्रों के भविष्य और राज्यों के अधिकारों का हवाला देते हुए टीवीके ने संविधान में बड़े बदलाव की वकालत की है। पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। पार्टी ने यह भी सुझाया है कि अगर ऐसा करने में कोई कानूनी अड़चन आती है,तो अंतरिम उपाय के तौर पर एक 'विशेष समवर्ती सूची' बनाई जाए। इससे राज्य सरकारों को मेडिकल एजुकेशन पर पूरा अधिकार मिल सकेगा। पार्टी ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री विजय पहले ही इस समाधान की रूपरेखा तय कर चुके हैं।

डीएमके को याद दिलाया उनका झूठा वादा

इस मुद्दे पर टीवीके ने राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी डीएमके पर भी जमकर निशाना साधा। टीवीके ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी छात्रों और जनता के साथ धोखे की राजनीति नहीं करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे महज वोटों के लालच में यह झूठा दावा कभी नहीं करेंगे कि 'हम खुद नीट रद्द कर देंगे।' गौरतलब है कि डीएमके ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि सत्ता में आते ही वे तमिलनाडु में नीट को खत्म कर देंगे।

स्टूडेंट्स गुस्से में इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे...उन पर लाठीचार्ज,पैलेट गन चलाई,वे आतंकवादी नहीं हमारा भविष्य,पीएम माफी मांगें : राहुल गांधी

नई दिल्ली,22 जुलाई 2026। राहुल गांधी दिल्ली के इंदिरा भवन में छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षाबलों ने छात्रों को बुरी तरह पीटा। ऐसा क्यों किया गया। नीट पेपर लीक से देश के 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स और उनके परिवार इस घटना से प्रभावित हुए हैं। नीट मामले में किसी भी को सजा नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 10 साल में 152 पेपर लीक देश में लीक हुए हैं। इनमें किसी भी मामले में किसी भी को सजा नहीं मिली। 1.4 लाख करोड़ भारत सरकार का एजुकेशन बजट है। 1.32 लाख करोड़ भारतीय परिवार नीट एग्जाम पर खर्च करते हैं। नीट का खर्च देश के शिक्षा बजट से ज्यादा है।

राहुल बोले...धर्मेंद्र प्रधान ने देश की शिक्षा व्यवस्था नष्ट कर दी है : राहुल ने कहा- जितना पैसा भारत सरकार शिक्षा बजट पर खर्च करती है, नीट एग्जाम पर भी उतना ही पैसा खर्च होता है, जो भारतीय परिवार देते हैं। सरकार साल भर टैक्स लेती है, इसी एजुकेशन बजट के लिए। धर्मेंद्र प्रधान ने देश की शिक्षा व्यवस्था नष्ट कर दी है। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह एजुकेशन दे, नौकरियां दे, बेहतर भविष्य दे।

राहुल बोले- गरीबों के लिए यह घटना कभी ना भूलने वाली है

राहुल ने कहा...स्टूडेंट्स 3 से 5 साल तक हर रोज 8 से 10 घंटे तैयारी करते हैं। फिर उन्हें बताया जाता है कि जिनके पास 40-40 लाख रुपए है वह पेपर खरीद सकता है। आपकी तैयारी और मेहनत का कोई मतलब है। जो पेपर लीक हुए हैं, यह इसको बताता है। स्टूडेंट्स यही सवाल कर रहे हैं कि पेपर लीक से 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। गरीबों के लिए यह घटना कभी ना भूलने वाली है।

राहुल बोले...देश के स्टूडेंट्स गुस्से में हैं,इसलिए प्रदर्शन

राहुल ने कहा कि कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स गुस्से में हैं। इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला कारण- एजुकेशन सिस्टम जो पूरी दुनिया में बेस्ट हुआ था। वह अब गड़बड़ हो गया है। बीते 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं। यह आंकड़ा 300 भी हो सकता है। कई बार पेपर लीक हुए, लेकिन उनका पता नहीं चला।

राहुल ने कहा...नीट मामले में किसी भी को सजा नहीं हुई...

राहुल ने कहा- 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स और उनके परिवार इस घटना से प्रभावित हुए हैं। नीट मामले में किसी भी को सजा नहीं हुई। 10 साल में 152 पेपर देश में लीक हुए हैं। इनमें किसी भी मामले में किसी भी को सजा नहीं मिली। 1.4 लाख करोड़ भारत सरकार का एजुकेशन बजट है। 1.32 लाख करोड़ भारतीय परिवार नीट एग्जाम पर खर्च करते हैं।

राहुल बोले...सुरक्षाबलों ने छात्रों को बुरी तरह से पीटा

राहुल ने कहा...हमारी एजुकेशन सिस्टम विश्व के सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में गिना जाता है। शिक्षा व्यवस्था पर काम करने की जरूरत है। छात्र सिस्टम सुधार की मांग कर रहे थे। देश की शिक्षा व्यवस्था आज गड़बड़ हो गई है।

कैबिनेट के बड़े फैसले : बंगाल में बनेगा एनआईए थाना

बीएसएफ को जमीन,आंगनवाड़ी पोषण योजना को अतिरिक्त बजट

कोलकाता,22 जुलाई 2026। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुरक्षा और पोषण से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) का थाना स्थापित करने, भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सरकारी भूमि हस्तांतरित करने के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडा खरीद के लिए अतिरिक्त बजट देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) का थाना स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। सरकार ने बताया कि आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद थाने की स्थापना का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि, इसे किस स्थान पर बनाया जाएगा, इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। फिलहाल, एनआइए का क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता के साल्टलेक में संचालित है, जहां से राज्य में दर्ज मामलों की जांच की जाती है।

सरकार का कहना है कि राज्य में एजेंसी के बढ़ते कार्यभार और जांच के दायरे को देखते हुए अलग थाना स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई। मंत्रिमंडल ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा प्रखंड के फतेहाबाद मौजा स्थित 0.588 एकड़ सरकारी भूमि स्थायी रूप से बीएसएफ को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा नदिया जिले के गोपालपुर में बीएसएफ की 56वीं बटालियन की सीमा चौकी स्थापित करने के लिए 0.42 एकड़ सरकारी भूमि स्थायी रूप से बीएसएफ को देने का निर्णय लिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भविष्य में भी आवश्यकता के अनुसार भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में संचालित पोषण कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए अंडा खरीद पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। फैसले के अनुसार, गर्म पका भोजन और सुबह के नाश्ते में अंडा उपलब्ध कराने के लिए माताओं के भोजन पर प्रति प्लेट दो रुपये और बच्चों के भोजन पर प्रति प्लेट दो रुपये अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। यह राशि पहले से निर्धारित बजट के अतिरिक्त होगी। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता में सुधार होगा और गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।

'कॉकरोचों' पर लाठीचार्ज...सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार,चीफ जस्टिस बोले...वीडियो देखने का वक्त नहीं,हमारा समय बर्बाद न करें

नई दिल्ली,22 जुलाई 2026। सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। बुधवार को एक वकील ने सीजेआई की अगुआई वाली 3 जजों की बेंच के सामने जनहित याचिका लगाई थी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा...'हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है। हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है।' जब वकील ने छात्रों के साथ मारपीट के वीडियो देखने का दूसरी बार अनुरोध किया तो सीजेआईने कहा, 'हमारा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए।' बता दें कि 15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा था, 'कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं, जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं।' इस टिप्पणी के बाद ही अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से अकाउंट बनाया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को संसद मार्च निकाला था। इस दौरान हजारों प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़े थे,इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और छात्रों को चोटें आई थीं।

छात्रों के मार्च पर पुलिस का एक्शन,आंसू गैस और वॉटर कैनन का इस्तेमाल

पटना,22 जुलाई 2026। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (आइसा) के नेतृत्व में आयोजित यह मार्च राजभवन की ओर बढ़ रहा था। प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी मांगें उठाने पहुंचे थे। पुलिस ने गांधी मैदान के पास मार्च को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर तनाव बढ़ गया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रदर्शनकारी छात्र जब गांधी मैदान स्थित होटल मौर्या के समीप पहुंचे,तब पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोका। इसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की तथा बहस की स्थिति बन गई। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए ताकि कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो और प्रदर्शन निर्धारित सीमा के भीतर रहे। स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वॉटर कैनन का उपयोग किया। पानी की तेज बौछारों के बावजूद कई छात्र मौके पर डटे रहे और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी जारी रखी। पुलिस का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और प्रदर्शन को आगे बढ़ने से रोकना था। इस दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन : यह प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में विभिन्न नारे लगाए और कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा संबंधी मुद्दों को प्रमुखता से उठाना था। आयोजकों के अनुसार,पटना में आयोजित यह प्रदर्शन दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में भी किया गया। छात्रों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में शिक्षा और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर युवाओं की चिंता समान है।

संपादकीय

फिर असहाय-निरुपाय दिखी दिल्ली

कथित राजनीतिक दल काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संसद चलो मार्च के समय प्रदर्शनकारियों ने जैसी हिंसा की, वह उनके अलावा उन सबको दिखी,जिन्हें केवल पुलिस की सख्ती दिखाई दी। इस संसद मार्च के दौरान हिंसा इसलिए हुई,क्योंकि भीड़ बेलगाम थी और उसमें छात्रों के साथ अराजक तत्व भी थे। इन तत्वों को मनमानी करने का अवसर इसलिए मिला,क्योंकि संसद मार्च का न तो कोई नेतृत्व करने वाला था और न ही भीड़ को निर्देशित करने वाला। जब दिल्ली की सड़कों पर हंगामा और हिंसा हो रही थी, तब सीजेपी के दो नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने और उन्हें ज्ञापन देने में लगे हुए थे।

यह ज्ञापन देने में उन्हें चार घंटे से ज्यादा लग गए। जो नेता बचे थे,उनमें से एक बर्गर खाने चले गए और जो मौके पर थे, उनका इरादा भीड़ को लेकर येन-केन-प्रकारेण संसद के करीब तक पहुंचना था। वे लगभग सफल भी हो गए, लेकिन इस जबरिया कोशिश में पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी, दोनों ही बड़ी संख्या में घायल हुए। इस दौरान जिस तरह दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए, उससे यही पता चलता है कि भीड़ में हिंसा फैलाने वाले भी शामिल थे और इसकी तैयारी से आए थे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में ऐसे तत्व हों तो हिंसा से बचना संभव नहीं होता। यही दिल्ली में हुआ-बीते सात साल में तीसरी बार। जितना यह सही है कि सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज किया, उतना ही यह भी कि भीड़ ने अराजकता का सहारा लिया और जमकर पथराव किया। स्पष्ट है कि पुलिस न तो भीड़ का अनुमान लगा सकी और न ही उनके इरादों का। कुछ ऐसा ही 2019-20 में शाहीन बाग धरने के समय हुआ था और 2021 में किसान आंदोलन और खासकर गणतंत्र दिवस पर उनकी ट्रैक्टर रैली के वक्त भी।

नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में एक मुख्य सड़क को घेरकर करीब सौ दिन तक धरना दिया गया था। इस धरने के कारण ही दिल्ली में तब भीषण दंगा हुआ,जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजधानी में थे। इस दंगे का पहला शिकार बने थे कांस्टेबल रतन लाल। इस दंगे में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इनमें एक आइबी कर्मी अंकित शर्मा भी थे। उनकी हत्या के आरोप में आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन को हाल में दोषी ठहराया गया है। वही ताहिर,जिसे मीडिया के एक हिस्से के साथ अन्य अनेक ने निर्दोष होने का सर्टिफिकेट दे दिया था। ऐसे ही सर्टिफिकेट तब बांटे गए थे, जब किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को कथित किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस रैली में शामिल अराजक ट्रैक्टर सवारों ने लाल किले पर धावा बोल दिया था। उस समय करीब सौ पुलिस वाले पीटे गए थे। तब भी अराजक भीड़ के सामने पुलिस और प्रशासन के साथ मोदी सरकार असहाय सी दिखी थी।

यह भी याद रखें कि शाहीन बाग धरने पर बैठे लोगों और किसान आंदोलनकारियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया था। जो किया भी था, वह समस्या बढ़ाने वाला रहा। उसने शाहीन बाग में धरनारत लोगों से बातचीत के लिए एक समिति गठित कर दी थी। इसी तरह तीन कृषि कानूनों की वैधानिकता जांचे बिना उनके अमल पर रोक लगा दी थी। इससे आंदोलनकारियों और उनके समर्थकों में संदेश गया कि उनका पक्ष सही है और फिर वे करीब एक साल तक दिल्ली को एक तरह से बंधक बनाकर बैठे रहे। वे तब लौटे,जब मजबूत मानी जाने वाली मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। इस बार क्या होगा,कहना कठिन है, क्योंकि सीजेपी समर्थक अब भी जंतर-मंतर पर जुटे हैं। इसी के साथ पंजाब के किसान संगठनों को अचानक यह पता चला कि अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते में उनके हित की अनदेखी हो सकती है,इसलिए वे दिल्ली जाने को मचल उठे।

संवाद से सशक्त होगा लोकतंत्र,हिंसा से नहीं

ललित गर्ग
पटपड़गंज,
नई दिल्ली

दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद भवन तक हाल के आंदोलन के दौरान जो तनाव,टकराव और हिंसक घटनाएं देखने को मिलीं,वे केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं,बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। पुलिस और प्रदर्शन कारियों के बीच टकराव, बैरिकेड तोड़ने के प्रयास,मेट्रो स्टेशन में जबरन प्रवेश की कोशिश, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग-ये सभी दृश्य उस लोकतांत्रिक संस्कृति के अनुरूप नहीं कहे जा सकते,जिसकी आधारशिला अहिंसा,संवाद और संवैधानिक मर्यादाओं पर रखी गई है। भारत आज आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 की ओर बढ़ रहा है। यह केवल आर्थिक महाशक्ति बनने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक परिपक्वता की कसौटी पर भी स्वयं को सिद्ध करने का अवसर है। यदि हम आज भी असहमति को हिंसा,टकराव और अराजकता के माध्यम से व्यक्त करेंगे,तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होगी। लोकतंत्र की शक्ति सड़क पर शक्ति-प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विचारों की शक्ति,संवाद की संस्कृति और संवैधानिक प्रक्रियाओं में निहित होती है।

राहुल गांधी द्वारा नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर चल रहे घरना-प्रदर्शन के दौरान अचानक अपने सहयोगी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के निकट धरने पर बैठना और संसद की बजाय सड़क को राजनीतिक संघर्ष का मंच बनाना अनेक गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जिस प्रकार इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के तथाकथित छात्रों एवं कार्यकर्ताओं ने संसद चलो मार्च के दौरान तनावपूर्ण,अराजक एवं हिंसक माहौल बनाने की घटनाएं सामने आईं,उससे यह आशंका बलवती हुई कि कुछ राजनीतिक शक्तियां भारत में भी नेपाल जैसी अराजक परिस्थितियां पैदा करने को उतावले हैं। सरकार की सतर्कता और सुरक्षा एजेंसियों की समय रहते की गई कार्रवाई से,कुछ कमियों के बावजूद,इस बड़े संकट को टाल दिया गया,अन्यथा दिल्ली लंबे समय तक हिंसा और अशांति की चपेट में आ सकती थी। देश पहले भी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के दौरान शाहीन बाग में लगभग सौ दिनों तक एक प्रमुख सड़क के अवरुद्ध रहने और उससे आम नागरिकों को हुई भारी कठिनाइयों का अनुभव कर चुका है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार निर्विवाद है, लेकिन उसका स्थान संसद,संवाद और संवैधानिक संस्थाएं हैं,न कि सड़क पर टकराव और अराजकता। विपक्ष यदि बार-बार ऐसे आंदोलनों को प्रोत्साहित करता है,तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि उसका उद्देश्य लोकतांत्रिक विमर्श को मजबूत करना है या राजनीतिक ध्रुवीकरण और अस्थिरता को बढ़ावा देना। जनता अपेक्षा करती है कि सभी दल संसद को सर्वोच्च मंच मानते हुए वहीं जवाबदेही सुनिश्चित करें।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण और निरस्त्र सभा करने का अधिकार देता है। यह अधिकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। किंतु प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य और मर्यादा भी जुड़ी होती है। प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है,लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस से टकराव करना, हिंसा फैलाना अथवा आम नागरिकों के जीवन को बाधित करना किसी भी दृष्टि से लोकतांत्रिक आचरण नहीं कहा जा सकता। यदि आंदोलन अपनी नैतिक शक्ति खो देता है,तो उसकी मांगें भी समाज की सहानुभूति खो बैठती हैं। यह भी उतना ही सत्य है कि लोकतंत्र केवल जनता के लिए नहीं,बल्कि सरकार के लिए भी उत्तरदायित्व का नाम है। सरकार को भी आंदोलनों को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर नहीं देखना चाहिए। जब भी किसी वर्ग,विशेषकर युवाओं और छात्रों में असंतोष उत्पन्न हो,तो उसका समय रहते समाधान खोजने का प्रयास होना चाहिए। संवाद के दरवाजे जितनी जल्दी खुलेंगे,टकराव की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी। लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य,संवेदनशीलता और संवाद की इच्छा होती है।

इतिहास साक्षी है कि भारत के अधिकांश सफल जनआंदोलन अहिंसा और संवाद की शक्ति से ही सफल हुए हैं। महात्मा गांधी ने विश्व को यह संदेश दिया कि सत्य और अहिंसा सबसे बड़े अस्त्र हैं। वर्ष 2011 का अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी इसका उदाहरण है। लाखों लोग सड़कों पर उतरे,लेकिन आंदोलन का नैतिक बल उसकी शांति और अनुशासन में था। उसी कारण सरकार को संवाद का रास्ता अपनाना पड़ा और पूरे देश में एक सकारात्मक बहस प्रारंभ हुई। इसके विपरीत जहां-जहां आंदोलनों ने हिंसा का मार्ग अपनाया,वहां उनका मूल उद्देश्य पीछे छूट गया और चर्चा केवल हिंसा तक सीमित होकर रह गई। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी कौन-सी शक्तियां हैं,जो सामान्य और भोली-भाली जनता एवं देश के युवाओं को हिंसा की ओर धकेल देती हैं? कौन-से तत्व आंदोलनों की दिशा बदलकर उन्हें अराजकता में परिवर्तित कर देते हैं? यह चिंता केवल सरकार की नहीं,पूरे समाज की होनी चाहिए। लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन यदि असहमति के मंच पर राष्ट्रविरोधी,अराजक अथवा हिंसक तत्व सक्रिय हो जाएं,तो उन्हें नियंत्रित करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनिवार्य दायित्व बन जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ अराजकता की स्वतंत्रता नहीं हो सकता।

संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। जंतर-मंतर लोकतांत्रिक विरोध का प्रतीक स्थल है। यदि इन दोनों के बीच हिंसा, तोड़फोड़ ण्वं अराजकता का दृश्य निर्मित होता है,तो यह केवल राजधानी की घटना नहीं रहती,बल्कि पूरे देश और विश्व के सामने भारतीय लोकतंत्र की छवि को प्रभावित करती है। लोकतंत्र की गरिमा इस बात में नहीं कि कौन अधिक आक्रामक है, बल्कि इस बात में है कि कौन अधिक संयमित और उत्तरदायी है। राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के दो पहिए हैं। यदि दोनों के बीच संवाद समाप्त हो जाएगा,तो लोकतंत्र टकराव का अखाड़ा बन जाएगा। विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, बल्कि रचनात्मक विकल्प प्रस्तुत करना भी है। उसी प्रकार सरकार का दायित्व केवल शक्ति प्रदर्शन करना नहीं,बल्कि असहमति को सम्मानपूर्वक सुनना भी है। लोकतंत्र में किसी की पूर्ण विजय या पूर्ण पराजय नहीं होती,यहां अंततः संवाद, सहमति और समाधान ही सबसे बड़ी जीत होती है।

छात्रों और युवाओं की समस्याओं का समाधान भी अत्यंत आवश्यक है। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा हैं। यदि उनकी आशाओं और अपेक्षाओं की उपेक्षा होगी, तो असंतोष स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह युवाओं से नियमित संवाद स्थापित करे, उनकी समस्याओं को समयबद्ध ढंग से सुने और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए। वहीं युवाओं को भी यह समझना होगा कि हिंसा उनके आंदोलन की सबसे बड़ी शत्रु है। पत्थर और लाठी किसी समस्या का समाधान नहीं करते,वे केवल संवाद के पुलों को तोड़ते हैं। आज आवश्यकता लोकतंत्र को अधिक परिपक्व बनाने की है। हमें ऐसी राजनीतिक संस्कृति विकसित करनी होगी जिसमें विरोध हो,लेकिन वैमनस्य न हो। मतभेद हों, लेकिन मनभेद न हों। संघर्ष हो,लेकिन हिंसा न हो। लोकतंत्र में बहस जितनी प्रखर होगी,राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। किंतु बहस का स्थान यदि हिंसा ले लेगी,तो लोकतंत्र की आत्मा आहत होगी। जंतर-मंतर से संसद तक जो कुछ हुआ,उसे लोकतांत्रिक आदर्श नहीं कहा जा सकता। यह किसी परिपक्व राजनीतिक सोच का भी परिचायक नहीं है। राष्ट्र निर्माण का मार्ग टकराव नहीं, सहयोग है। हिंसा नहीं,सहमति है। उग्रता नहीं,उदारता है। इसलिए आवश्यक है कि सभी पक्ष अपने-अपने आग्रहों से ऊपर उठकर राष्ट्हित को सर्वोपरि रखें। आज देश को ऐसे नेतृत्व और ऐसी जनचेतना की आवश्यकता है जो संवाद को संघर्ष से ऊपर रखे। सरकार उदारता और संवेदन शीलता दिखाए,आंदोलन कारी संयम और अनुशासन अपनाएं तथा राजनीतिक दल अल्पकालिक लाभ के बजाय लोकतंत्र की दीर्घकालिक मजबूती को प्राथमिकता दें। यही भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की वास्तविक पहचान भी है और भविष्य की आवश्यकता भी। अंततः यही कामना की जानी चाहिए कि जिन शक्तियों के कारण आंदोलनों में हिंसा और टकराव का वातावरण बनता है, उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो। सभी पक्ष संवाद की मेज पर बैठें, अपनी बात तर्क, तथ्यों और संवैधानिक मर्यादाओं के साथ रखें तथा समाधान का मार्ग खोजें। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय किसी पक्ष की जीत नहीं होती, बल्कि वह क्षण होता है जब विरोधी पक्ष भी एक-दूसरे की बात सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही आदर्श लोकतंत्र की पहचान है और यही विकसित भारत की सबसे मजबूत बुनियाद भी है।

क्या सत्ता का लंबा सफर भाजपा के लिए चुनौती बनता जा रहा है?

लोकतंत्र,जनादेश और जनता की अपेक्षाओं का विश्लेषण

जनादेश से जनआक्रोश तक?
भाजपा के लंबे शासन पर उठते सवाल
लंबे शासन की कीमत,क्या जनता का भरोसा कमजोर पड़ रहा है?
क्या सत्ता का आत्मविश्वास अहंकार में बदल रहा है?
लोकतंत्र के आईने में भाजपा

रवि सिंह
कोरिया,छत्तीसगढ़

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ जनता ही अंतिम निर्णायक होती है, कोई भी राजनीतिक दल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी असली ताकत जनता के विश्वास से आती है,जिस दिन जनता का विश्वास डगमगाने लगता है,उसी दिन सबसे मजबूत राजनीतिक किला भी कमजोर पड़ने लगता है,भारतीय राजनीति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आज़ादी के बाद दशकों तक कांग्रेस देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति रही, ऐसा समय भी था जब यह माना जाने लगा था कि कांग्रेस को सत्ता से हटाना लगभग असंभव है,लेकिन समय बदला, जनता का मूड बदला और वही कांग्रेस, जो कभी अपराजेय मानी जाती थी,धीरे-धीरे सत्ता से बाहर होती चली गई, 2014 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को भारी जनादेश दिया,भ्रष्टाचार, महंगाई,नीति-निर्णय में सुस्ती और मजबूत नेतृत्व की तलाश जैसे मुद्दों ने भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन दिलाया, 2019 में भी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले से भी बड़ा जनादेश मिला,लेकिन अब,लगातार लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद,यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भाजपा भी उसी दौर की ओर बढ़ रही है, जहाँ जनता की अपेक्षाएं और सरकार का आत्मविश्वास आमने-सामने खड़े दिखाई देने लगते हैं?

भारत का लोकतंत्र लगातार विकसित हो रहा है, सरकारों का मूल्यांकन उनके कार्य,नीतियों और जनता के अनुभवों के आधार पर होता है, लंबे समय तक सत्ता में रहना किसी भी दल के लिए अवसर भी है और परीक्षा भी,यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं,आलोचनाओं और संवाद को गंभीरता से लेती है,तो उसका जनसमर्थन मजबूत हो सकता है,यदि जनता को लगता है कि उसकी चिंताओं की अनदेखी हो रही है,तो वह चुनाव के माध्यम से अपना निर्णय बदल सकती है,अंततः लोकतंत्र की असली शक्ति किसी एक दल, नेता या विचारधारा में नहीं,बल्कि नागरिकों के मताधिकार,संविधान और शांतिपूर्ण जनभागीदारी में निहित है। सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाएँ और जनता का अधिकार ही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान हैं।

सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा उसका लंबा कार्यकाल होता है- विपक्ष में रहकर सरकार की आलोचना करना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन लंबे समय तक सत्ता में बने रहना कहीं अधिक कठिन होता है,शुरुआत में जनता उम्मीदों के साथ सरकार को समय देती है, लेकिन जैसे-जैसे कार्यकाल बढ़ता है,अपेक्षाएँ भी बढ़ती जाती हैं, लंबे समय तक शासन करने वाली लगभग हर सरकार के सामने कुछ सामान्य चुनौतियाँ आती हैं जनता में सत्ता-विरोधी भावना का उभरना,संगठन और सरकार के बीच संवाद में कमी,स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही कमजोर होना,यह धारणा बनना कि सरकार जनता की बात कम और अपनी उपलब्धियों की चर्चा अधिक कर रही है, यही परिस्थितियाँ कभी कांग्रेस के सामने भी आई थीं और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि किसी भी लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले दल को इन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है।

क्या भाजपा के सामने भी वही चुनौती है?- भाजपा समर्थक सरकार की उपलब्धियों की लंबी सूची प्रस्तुत करते हैं,बुनियादी ढाँचे का विस्तार, डिजिटल भुगतान,कई कल्याणकारी योजनाएँ, विदेश नीति, रक्षा क्षेत्र में कुछ फैसले,सड़क और रेलवे परियोजनाएँ जैसे विषय अक्सर उसकी उपलब्धियों में गिनाए जाते हैं,दूसरी ओर, आलोचक महंगाई,बेरोजगारी,सामाजिक तनाव, विपक्ष के साथ टकराव,संस्थाओं की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,किसानों और युवाओं की चिंताओं जैसे मुद्दे उठाते हैं,लोकतांत्रिक राजनीति में दोनों तरह की बातें साथ-साथ मौजूद रहती हैं, किसी भी सरकार का मूल्यांकन केवल उपलब्धियों या केवल आलोचनाओं से नहीं, बल्कि दोनों के संतुलन से किया जाता है।

क्या जनता की नाराज़गी बढ़ रही है?- जब किसी सरकार के खिलाफ लगातार अलग-अलग वर्ग आवाज उठाने लगें,तो यह राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है,कर्मचारी,किसान, युवा, व्यापारी,छात्र या अन्य समूह यदि अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करते हैं, तो सरकार के लिए यह अवसर भी होता है और चेतावनी भी, हर विरोध यह सिद्ध नहीं करता कि सरकार अलोकप्रिय हो गई है,लेकिन लगातार बढ़ते असंतोष को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करना भी किसी सरकार के लिए उचित नहीं माना जाता।

जंतर-मंतर और विरोध की राजनीति- भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार देता है, लोकतंत्र में सरकार से असहमति होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है, हालाँकि,हर प्रदर्शन की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है,यदि किसी विरोध प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग हुआ हो,तो उसकी वैधता और आवश्यकता का आकलन तथ्यों,परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, किसी भी एक घटना से व्यापक निष्कर्ष निकालने से पहले उसके सभी पक्षों को देखना आवश्यक है।

क्या सरकार आलोचना सुन रही है?-किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की मजबूती केवल चुनाव जीतने में नहीं,बल्कि आलोचना सुनने और आवश्यक सुधार करने की क्षमता में भी होती है, यदि सरकार के समर्थक हर आलोचना को देशविरोध या राजनीति मानकर खारिज कर दें, तो इससे वास्तविक समस्याओं पर चर्चा कमजोर हो सकती है,दूसरी ओर, यदि विपक्ष हर सरकारी निर्णय को बिना तथ्यों के गलत ठहराए,तो वह भी रचनात्मक लोकतांत्रिक विमर्श को नुकसान पहुँचाता है,स्वस्थ लोकतंत्र में नीतियों की आलोचना और उपलब्धियों की सराहना—दोनों के लिए स्थान होना चाहिए।

क्या सत्ता का आत्मविश्वास कभी अहंकार में बदल सकता है?-राजनीतिक इतिहास बताता है कि लंबे समय तक लगातार चुनाव जीतने के बाद किसी भी दल के भीतर यह जोखिम पैदा हो सकता है कि वह अपनी लोकप्रियता को स्थायी मानने लगे,यदि ऐसा होता है, तो जनता के साथ संवाद कमजोर पड़ सकता है, हालाँकि,यह कहना कि कोई विशेष दल निश्चित रूप से अहंकार में आ गया है,एक राजनीतिक राय होगी,स्थापित तथ्य नहीं,इसका आकलन मतदाता अपने अनुभवों,चुनावी व्यवहार और सरकार के कामकाज के आधार पर करते हैं।

भाजपा समर्थक और आलोचक-दोनों की भूमिका-लोकतंत्र में समर्थक और आलोचक दोनों आवश्यक हैं, समर्थक सरकार की उपलब्धियाँ सामने रखते हैं,जबकि आलोचक कमियों की ओर ध्यान दिलाते हैं, यदि समर्थक हर निर्णय का बिना प्रश्न किए समर्थन करें या आलोचक हर निर्णय का बिना विश्लेषण विरोध करें,तो दोनों स्थितियाँ लोकतांत्रिक बहस को कमजोर करती हैं,किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए तथ्य-आधारित चर्चा अधिक उपयोगी होती है।क्या जनता के पास विकल्प हमेशा रहता है?- भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा सत्य यही है कि अंतिम निर्णय मतदाता करता है,इतिहास में कई ऐसे अवसर आए हैं जब बहुत मजबूत मानी जाने वाली सरकारें चुनाव हार गईं,और कई बार कठिन परिस्थितियों के बावजूद सरकारें दोबारा जनादेश लेकर लौटीं,इसलिए यह मान लेना कि कोई भी दल हमेशा सत्ता में रहेगा या कोई दल कभी वापस नहीं आएगा—दोनों ही राजनीतिक रूप से निश्चित निष्कर्ष नहीं हैं, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही है कि जनता समय-समय पर अपना निर्णय बदल भी सकती है।

दुनिया में

प्रोफेसर शाम लाल कौशल
रोहतक,हरियाणा

दुनिया में कोई ऐसा मिला
दुनिया में कोई कैसा मिला
दुनिया में मुझे कोई ऐसा
और न जाने कैसा मिला!
कहीं मिली गरीबी तो
कहीं बहुत पैसा मिला!
कहीं मिली बे इंसाफी
कहीं ठीक फैसला मिला
कहीं मिल गया कोई साथी
कहीं मैं अकेला ही चला
लोग आते जाते रहे यहां
दुनिया का मेला चलता रहा
कहीं मिली मुझे सफलता
और कहीं मैं हाथ मलता रहा
जिंदगी थी एक लंबा सफर
इस पर कभी कैसे और फिर
कभी कैसे मैं चलता ही रहा
जिसे मैंने बनाया अपना ही
हाथ से वह फिसलता रहा
उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा
रात रात भर तारे गिनता रहा।
मेहनत का दामन मैंने छोड़ा नहीं
कोयला हो या हीरा चुनता रहा।
यह जिंदगी थी एक लंबा सफर
इस सफर पर जैसे कैसे चलता रहा।

सुविचार

जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ो में शर्म आती है, तो गंदे और मैले विचारों में भी शर्म आनी चाहिए।
स्वामी विवेकानंद

भारत में नया राष्ट्र कुर्सीस्तान का उत्थान

आत्माराम यादव
नर्मदापुरम,
मध्यप्रदेश

भारत के नेताओं के प्राण कुर्सियों में बसे है,कुर्सी गई,नेता प्राणहीन हो जाता है। देवताओं का आए दिन असुरों के हाथों पराजित होना पड़ता था ओर इन्द्र अपना इंद्रासन छोड़ श्रीविष्णु की शरण में जाते तब देव ओर दनुजों की हालत 52 पत्तों के जैसी थी जिसमें हुकुम,पान चिड़ी व ईट चार सेट में एक्का से दहला तक ओर चार बादशाह,चार रानी,चार रानी ओर एक जोकर की भांति कभी देवता इन पत्तों के रूप में दानवों के हाथों में पीसे जाते तो कभी दानव देवताओं के हाथो पिस रहे होते तब विष्णु जी ने दानवों के हाथों देवता न पिसे इसके लिए उन्हे अमर बनाने समुद्र मंथन कराया तब आखरी बार देवताओं ओर दानवों ने मंडराचल से समुद्र को मथा। मथने से अमृत निकला विष्णु जी ने देवताओ ओर दानवों की अलग पंक्ति लगा मोहनी रूप रख देवताओं को अमृत पिला अमर कर दिया। श्रीनारायण ने देवताओं को अजर अमर करने हेतु मोहनी रूप रख असुरों के साथ छल कर देवताओं की कुर्सी को अमरता दे दी। इन्द्र की कुर्सी बचाने के लिए दुनिया का पहला छल जगत ने देखा तभी से भारत में एक नए राष्ट्र कुर्सीस्थान का बीजारोपन हुआ। छल से कुर्सी बचाने का चलन तभी से दुनिया के सामने आया ओर भारत के नेता पूरी ताकत से कुर्सीस्थान बनाने में सफल भी हुये है, बस अंतर इतना है कि विष्णु जी ने यह छल असुरों की ताकत को नष्ट कर देव ताकत स्थापित करने के लिए किया था, पर आज उल्टा चलन शुरू हुआ जिसमे मनुष्य के रूप में सारे असुर देवताओं का मेकअप करके अपनी प्रजा के शरीर में दौड़ रहे खून की आखिरी बूंद तक चूसने का शोषण करने अंगद के पैर कि तरह जाम चुके है।

भारत आज इसी छल-कपट,अत्याचार ओर शोषण की ताकत पर कुर्सीस्थान बनने जा रहा है,इसमे कोई नई बात नहीं है। भारत जम्बूदीप का हिस्सा रहा है पहले जंबुदीप कुर्सीस्थान बना ओर कुर्सियों कि ललक ने जम्बूदीप भारत के खण्ड-खण्ड किए जिसमें ईरान,अफगानिस्थान,पाकिस्तान,हिंदुस्तान, नेपाल,भूटान,म्यामर,श्रीलंका,मालद्वीप, थाइलेंड,मलेशिया,इन्डोनेशिया,कंबो डिया, वियतनाम ओर लायोस आदि 15 देश बने यानि हमारे अखण्ड जंबुदीप राष्ट्र के खण्ड-खण्ड 15 टुकड़े दुनिया में 15 देशों मे बट गए। इन 15 देशों में करोड़ों कुर्सिया नेताओं,प्रशासनिक अधिकारिओ आदि को मिल गई। अंग्रेजों कि गुलामी से मुक्त हुये तो पाकिस्तान, बांग्लादेश ओर भारत के सयुंक्त क्षेत्रफल अखण्ड भारत न पाकर नेताओं के कुर्सी प्रेम के कारण 3 देशों में बट गए। इससे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा,अगर उनके खून में राष्ट्र प्रेम होता तो जंबुदीप के 15 खंड अर्थात 15 देश नहीं होते। हम कुर्सियों के लिए देश में जितने प्रदेश है उन प्रदेशों को जिले के रूप में करने को तत्पर है जिलों को गाँव बनाकर वहाँ कलेक्टर बनाकर अपने कुर्सी प्रेम को जिंदा रखे है,हमें देश नही कुर्सी से प्रेम है, कुर्सी के लिए जो कीमत चुकानी हो हम चुकाने को तैयार है किन्तु कुर्सी गवाना नहीं चाहते है।

जंबुद्वीप की महिमा वेद पुराणों ओर शास्त्रो में होने से आज भी हम सनातन धर्म के इस सत्य को सदियों से स्वीकारते आ रहे है ओर किसी भी सनातनी के घर परिवार में शुरू होने वाली हर छोटी बड़ी पूजापाठ, यज्ञ अनुष्ठान, शादी विवाह आदि मांगलिक आयोजनों को सम्पन्न करने वाले पंडित पुरोहित ओर आचार्य आदि देवताओ का आव्हान करते समय यह संकल्प दिलाते है कि--जम्बद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते अमुक नगरे,,अमुक राज्ये अमुक गौत्रे अर्थात आज भी हमारे पूर्वजों की धरोहर को हम संभाल नहीं पाये किन्तु पूर्वजों की इस विरासत जंबुद्वीप को एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं किए है। यह हमारा राष्ट्र प्रेम रहा है न की कुर्सी प्रेम,किन्तु जैसे हाथी के दाँत देखने के ओर खाने के होते है,वैसे ही नेताओं के दाँत भी हाथी जैसे है, इसलिए जंबुद्वीप से कब कैसे अलग हो 15 राष्टो को कुर्सीस्तान बनने दिया यह कतई गौरव की बात नहीं है पर हाँ इन राष्ट्रों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक,सरपंच से लेकर सभी के लिए युद्धस्तर पर कुर्सियों की जरूरत पैदा करने वाले जरूर बने है। इन सभी देशों में दिन दूना रात चोगुना कुर्सी उत्पादन बढ़ता गया ओर हम जम्बूद्वीप वासी भले भारत राष्ट तक सीमित रह गये किन्तु कुर्सी का व्यापार राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय तक पहुचाने में हमारी दौड़ थमी नहीं है ओर जंबुद्वीप का यश गा रहे है।

भारत के नेताओं ने अपने घर परिवार से लेकर मोहल्ले,गाँव,कस्बे, शहर राजधानी तक के जर्रे-जर्रे में कुर्सियां बो दी है ओर हुकूमत के नशे में इतराते बलखाते नेताओं का प्रेम देश के लिए अपने प्राण लुटाने वाले किसी शहीद के लिए नहीं बल्कि आजादी मिलने के बाद सत्य ओर अहिंसा को गिरवी रखकर द्वेष ड्ड छल कपट बेईमानी की विचारधारा से देश का बंटवारा कर देश को झुकने के लिए विवश किए जाने की नाराजगी से शहीद हुए महात्मा गांधी के उन कागजों से है जिस पर वे देश की करेंसी के रूप में छपे है,ये सारे नेता कुर्सी बचाने के लिए महात्मा गांधी छपे नोटों के लिए अपने प्राण दे सकते है या किसी के भी प्राण ले सकते है। इनके लिए कुर्सीस्तान की महिमा न्यारी है इसलिए वे कुर्सियों से कुर्सियां पैदा कर रहे है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

झमाझम बारिश से नदी-नाले उफान पर कई मार्ग बाधित,नदी में फंसी ट्रैक्टर

दो दिनों की बारिश से बदला मौसम का मिजाज,अंबिकापुर में 24 घंटे में 102 मिमी वर्षा दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

उत्तर छत्तीसगढ़ में मानसून ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है। सरगुजा संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले दो दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मंगलवार देर शाम से शुरू हुई तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई नदी-नाले उफान पर हैं, जबकि अनेक पुलियों और रपटों के ऊपर पानी बहने से आवागमन बाधित हो गया है। कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी पांच दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। लंबे समय से कम बारिश का सामना कर रहे सरगुजा संभाग के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है। जानकारी के अनुसार, सरगुजा जिले में अब तक औसत से करीब 58 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई थी, लेकिन पिछले दो दिनों की बारिश से स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। जिला मुख्यालय अंबिकापुर में पिछले 24 घंटों के दौरान 102 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के कारण शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। लगातार हो रही बारिश के कारण सरगुजा संभाग की कई नदियां और नाले उफान पर हैं। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर क्षेत्र के मोहनपुर में झींक नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र के रसौकी मार्ग में बरंगा नदी में बाढ़ आने से आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। यहां नदी पर पुल नहीं होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड में मान नदी के उफान पर होने से पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। इसके कारण बिरिमकेला, महेशपुर, नकना, बटईकेला और सरमना सहित कई गांवों के लोगों को आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से नदी-नालों को पार नहीं करने की अपील की है।

बाढ़ में फंसी ट्रैक्टर

सीतापुर क्षेत्र के केसला में मांढ़ नदी में अचानक जलस्तर बढऩे से रेत से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी के बीच फंस गई। बताया जा रहा है कि चालक रेत निकालने के लिए नदी में उतरा था,लेकिन इसी दौरान तेज बारिश के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढऩे लगा। स्थिति बिगड़ते देख चालक ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि ट्रैक्टर और रेत से भरी ट्रॉली नदी में फंसी हुई है और जलस्तर बढऩे के कारण उसे बाहर निकालना संभव नहीं हो सका है।

बादलों से घिरा मैनपाट,बढ़ी प्राकृतिक सुंदरता

लगातार बारिश से सरगुजा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट पूरी तरह बादलों की चादर में लिपट गया है। पहाड़ी क्षेत्र में फैली धुंध और हरियाली ने यहां की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा दिया है। मानसून के इस मौसम में मैनपाट का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कई दिनों तक धूप नहीं निकलने और ठंडे मौसम के कारण यहां का वातावरण बेहद रमणीय हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और जलभराव एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।

दिल्ली आंदोलन में शामिल होने जा रहे सरगुजा के युवक की सडक़ हादसे में मौत,साथी गंभीर

सोनम वांग्चुक के धरने में शामिल होने बाइक से निकले थे दोनों युवक

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

दिल्ली के जंतर-मंतर में आयोजित आंदोलन में शामिल होने जा रहे सरगुजा जिले के दो युवक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सडक़ दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई,जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के गांव में शोक की लहर फैल गई है। परिजन घायल युवक और मृतक के शव की जानकारी लेने अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। जानकारी के अनुसार,सीतापुर विकासखंड के ग्राम आरा निवासी दीपक सिंह (18 वर्ष) और उसका साथी सुरेश सिंह नीट पेपर लीक मामले तथा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांग्चुक के आंदोलन के समर्थन में दिल्ली जा रहे थे। दोनों युवक 18 जुलाई की रात पल्सर बाइक से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। बताया जा रहा है कि दोनों ने यात्रा शुरू करने से पहले सोशल मीडिया पर आंदोलन के समर्थन में पोस्ट भी साझा की थी,जिसमें उन्होंने लिखा था कि 'हमारे सपने बिकाऊ नहीं हैं,हम न्याय लेकर रहेंगे। 'यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में उनकी बाइक सडक़ हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि दीपक सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुरेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक का अलीगढ़ के एक अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे के बाद अलीगढ़ पुलिस ने युवकों के पास मिले पहचान पत्र और दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान की। इसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने सीतापुर पुलिस से संपर्क कर घटना की जानकारी दी। सीतापुर पुलिस ने ग्राम आरा के सरपंच अजीत तिर्की के माध्यम से मृतक एवं घायल युवक के परिजनों को हादसे की सूचना पहुंचाई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार के सदस्य तत्काल अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। गांव में भी शोक का माहौल है और बड़ी संख्या में ग्रामीण मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। सीतापुर पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस से सडक़ दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई है। परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है तथा आगे की कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही है। युवा दीपक सिंह की असामयिक मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक व्याप्त है। ग्रामीणों ने इसे एक प्रतिभाशाली और जागरूक युवक की दुखद क्षति बताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

अमेरा कोल माइंस में विजिलेंस का छापा,जांच शुरू

लाखों रुपये की अनियमितता उजागर होने की संभावना

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

कोयला चोरी और कथित अवैध वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच मंगलवार को एसईसीएल की विजिलेंस टीम ने खदान परिसर में छापामार कार्रवाई की। बिलासपुर से पहुंची टीम ने एसईसीएल अमेरा कोल खदान में छापा मार कर विभिन्न दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ समय से अमेरा कोल माइंस में कोयला परिवहन, पार्किंग शुल्क और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों में कोयला चोरी, रिकॉर्ड में गड़बड़ी तथा वाहनों से अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन शिकायतों के आधार पर एसईसीएल मुख्यालय स्तर पर मामले को गंभीरता से लेते हुए विजिलेंस जांच के निर्देश दिए गए। विजिलेंस टीम के खदान पहुंचते ही अधिकारियों और कर्मचारियों में हडक़ंप की स्थिति बन गई। टीम द्वारा विभिन्न अभिलेखों, परिवहन रजिस्टर, डिस्पैच रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में कुछ अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी गड़बड़ी की पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों का दावा है कि जांच में लाखों रुपये की अनियमितता का खुलासा हो सकता है। टीम खदान संचालन, कोयला परिवहन और भुगतान संबंधी रिकॉर्ड का मिलान कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इधर,एसईसीएल प्रबंधन ने विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर अलग पक्ष रखा है। प्रबंधन का कहना है कि खदान में ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के कारण विजिलेंस टीम पहुंची है और सिस्टम से संबंधित दस्तावेजों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है। प्रबंधन ने कोयला चोरी और अवैध वसूली के आरोपों पर फिलहाल कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है। गौरतलब है कि अमेरा कोल माइंस में पिछले कुछ समय से अव्यवस्था, बदहाल सडक़, कोयला परिवहन में बाधा और कथित अवैध वसूली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में विजिलेंस की यह कार्रवाई कई महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने ला सकती है।

अमेरा कोल माइंस में अव्यवस्था से कोयला उत्पादन प्रभावित,अवैध वसूली के आरोप से वाहन मालिक परेशान

बदहाल सडक़ और जल निकासी की समस्या से प्रतिदिन हजारों टन कोयला परिवहन बाधित,खदान के बाहर लगी ट्रकों की लंबी कतार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

लखनपुर स्थित एसईसीएल की अमेरा कोल माइंस में अव्यवस्था,बदहाल सडक़ और कथित अवैध वसूली के आरोपों के कारण कोयला उत्पादन और परिवहन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। खदान में आने वाले ट्रक चालकों और वाहन मालिकों ने आरोप लगाया है कि पार्किंग के नाम पर प्रति वाहन 600 रुपये की वसूली की जा रही है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार,अमेरा कोल माइंस से प्रतिदिन लगभग 4,000 टन कोयले की सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन लगातार बारिश, सडक़ पर कीचड़ और जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण वर्तमान में केवल 300 से 400 टन कोयले की ही सप्लाई हो पा रही है। इससे डीओ होल्डरों और ट्रांसपोर्टरों को प्रतिदिन भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि खदान तक पहुंचने वाली सडक़ की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। बरसात के कारण सडक़ पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गई है, जिससे ट्रकों का आवागमन मुश्किल हो गया है। कई ट्रक घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं और कई बार वाहन खराब होने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। स्थानीय लोगों और ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि खदान तक पहुंचने वाली सडक़ का निर्माण कार्य बरसात शुरू होने से पहले पूरा किया जाना था,लेकिन समय पर कार्य पूरा नहीं होने के कारण अब स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। इसके चलते खदान के बाहर चार किलोमीटर से अधिक लंबी ट्रकों की कतार लग गई है। गौरतलब है कि लगभग छह महीने पहले ग्रामीणों के विरोध के बावजूद अमेरा कोल माइंस के विस्तार को मंजूरी दी गई थी। उस समय स्थानीय लोगों ने सडक़,प्रदूषण और आधारभूत सुविधाओं को लेकर कई आशंकाएं जताई थीं।

वर्तमान हालात को देखते हुए ग्रामीणों की चिंताएं सही साबित होती नजर आ रही हैं। लिफ्टर मो. समीम और ट्रक चालक धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि सडक़ और अव्यवस्था के कारण ट्रांसपोर्ट कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं पार्किंग शुल्क के नाम पर हो रही कथित वसूली से वाहन मालिकों में नाराजगी बढ़ रही है। इस संबंध में अमेरा कोल खदान के सब एरिया मैनेजर ओमप्रकाश अटल ने बताया कि बारिश के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। सडक़ और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कोयला परिवहन और उत्पादन जल्द सामान्य हो सके। हालांकि अवैध वसूली के आरोपों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात भी कही गई है।

पत्नी की हत्या करने वाले विचाराधीन बंदी की बिगड़ी तबियत,मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान विचाराधीन बंदी की मौत हो गई। वह पत्नी की हत्या के मामले में बलरामपुर-रामानुजगंज जेल में बंद था। तबियत खराब होने पर उसे केन्द्रीय जेल अंबिकापुर से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पेंडारडीह निवासी विफना कोरवा पिता स्व. जरहा 40 वर्ष रामानुजगंज जेल में बंद था। उस पर 1 जनवरी 2025 को पत्नी की जलती लकड़ी से दागकर हत्या करने का आरोप लगा था। 20 जुलाई को तबियत खराब होने की सूचना पर उसे अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। सेंट्रल जेल से उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी बीच 21 जुलाई की रात करीब 12 बजे उसकी मौत हो गई। बुधवार को पीएम पश्चात उसका शव उसके परिजन को सौंप दिया गया।

प्रताडऩा से तंग आकर महिला ने की थी आत्महत्या,पति पर केस दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

पति का दूसरी लडक़ी से प्रेम संबंध और तलाक के लिए प्रताडऩा से तंग आकर विवाहिता आत्महत्या कर ली थी। दरिमा थाना पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी पति के विरूद्ध आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का मामला दर्ज कर लिया है,और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक,दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम मोतीपुर की शिवकुमारी पति डेकानंद सिंह 24 वर्ष पति के प्रताडऩा से तंग आकर बीते 11 अप्रैल को ग्राम लिबरा में स्थित घुनघुट्ठा डैम में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में थाना दरिमा में मर्ग कायम करके पुलिस ने जांच में लिया था। पुलिस ने मृतिका के भाई, मां,बहन,जीजा सहित अन्य का बयान लिया।

निजीकरण एवं ठेका प्रथा के विरोध में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन,कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों एवं स्वास्थ्य विभाग में संभावित निजीकरण,आउटसोर्सिंग तथा ठेका प्रथा के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया।

जिले के सभी विकासखंडों से बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी घड़ी चौक, अंबिकापुर में एकत्रित हुए, जहां से रैली निकालकर मुख्यमंत्री,स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कर्मचारियों ने वर्ष 2023 के अनिश्चितकालीन कामबंद आंदोलन के पश्चात शासन द्वारा दिए गए आश्वासनों को शीघ्र पूरा करने की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों ने पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने, स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण, आउटसोर्सिंग एवं ठेका प्रथा पर रोक लगाने, एक पाली में ओपीडी संचालन, आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली में व्यावहारिक सुधार,पदनाम परिवर्तन,रेडिएशन भत्ता, जोखिम भत्ता,स्वास्थ्य संस्थाओं में कर्मचारियों हेतु आवास की व्यवस्था,समय पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान, संविदा कर्मचारियों के लिए नियमित भर्ती में 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने,समान कार्य के लिए समान वेतन तथा स्वास्थ्य आयोग के गठन सहित विभिन्न मांगों को प्रमुखता से उठाया।

इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। संघ ने बताया कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए 25,000 रुपए प्रतिमाह निश्चित मानदेय एवं कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।

साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना में वेतनमान पुनर्निर्धारण संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया जा चुका है,किंतु आज तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। संघ ने शासन से मांग की कि अनुमोदित प्रस्ताव के अनुरूप तत्काल आदेश जारी कर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को उसका लाभ प्रदान किया जाए। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारी निरंतर जनस्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित भाव से संचालित कर रहे हैं, किंतु उनकी वर्षों पुरानी न्यायोचित मांगों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। यदि शासन द्वारा शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रदेशव्यापी एवं उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। इस अवसर पर संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल कुमार पाण्डेय सहित प्रांत,जिला एवं विकासखंड स्तर के संघ पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, स्टाफ नर्स, एएनएम, आरएचओ,लैब टेक्नोलाजिस्ट, फार्मासिस्ट सहित बड़ी संख्या में नियमित एवं अनियमित स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान तीन महिलाओं के गले से चेन व जीवतिया चोरी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सीतापुर थाना क्षेत्र में 17-18 जुलाई के बीच भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा दौरान तीन महिलाओं के गले से सोने का चेन पार करने का मामला प्रकाश में आया है। एक मामले में आसपास मौजूद लोगों ने दो संदिग्ध महिलाओं को पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द किया है,जो भीड़ का फायदा उठाकर चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देने में लगी थीं। इनके पास से सास-बहू के गले से पार किया गया सोने का चेन और जिवतिया बरामद हुआ।

जानकारी के अनुसार ग्राम प्रतापगढ निवासी शांति गुप्ता 17 जुलाई को ग्राम चलता बरपारा में रथ यात्रा देखने के लिए शाम को करीबन 6 बजे अपने परिवार के साथ गई थी। इसी दौरान अज्ञात द्वारा गले से सोने का जीवतिया पार कर दिया। रथ स्थान में भीड़ रहने के कारण इसका पता नहीं चला। आधे घंटे बाद जब गले में 4 जीवतिया के साथ पहने हुए माला के नहीं होने का आभास हुआ तो इसकी जानकारी साथ में गए परिवार के सदस्यों को दी। आसपास तलाश के बाद भी स्नेचर का पता नहीं चला। चोरी गए जीवतिया की कीमत करीब 80 हजार रुपये बताई गई है।

इसके बाद 18 जुलाई को ग्राम गिरहुलडीह में सास-बहू के गले से सोने का चेन और जिवतिया पार होने का मामला सामने आया। गिरहुलडीह की राधिका गुप्ता और अपनी बहू भारती गुप्ता के साथ घटना तिथि को शाम करीब 4 बजे रथ यात्रा देखने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ गई थी।

रथ में विराजमान प्रभु जगन्नाथ का पूजा करते समय दो महिलाएं राधिका के गले से सोने का चेन और भारती के गले से सोने का जिवतिया लॉकेट चोरी करने के बाद भाग रही थीं। अन्य लोगों के सहयोग से पकडक़र पूछताछ करने पर इन्होंने अपना नाम अनिता बाई निवासी ग्राम पतईकेला बगीचा व मानकी गिरी निवासी ग्राम दोरना लुण्ड्रा का होना बताया। इनके पास सास-बहू के गले से पार किया गया करीब 2 लाख 50 हजार रुपये का सोने का लॉकेट और जिवतिया मिला। पुलिस ने दोनों महिलाओं के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है,और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करके जांच कर रही है।

छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रधानमंत्री का पुतला दहन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर छात्रों पर कथित लाठीचार्ज,कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि संसद की ओर प्रदर्शन के लिए जा रहे छात्रों पर दिल्ली में पुलिस कार्रवाई की गई,जिसमें कई छात्र घायल हुए। कांग्रेस सांसद इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे थे। पार्टी के अनुसार,बाद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के समक्ष धरना दिया,जहां से उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान शफी अहमद,द्वितेंद्र मिश्रा, हेमंत सिन्हा, अरविंद सिंह 'गप्पू', भानुप्रताप सिंह, विनय शर्मा, इंद्रजीत सिंह धंजल, मोहम्मद इस्लाम, रामविनय सिंह, जगन्नाथ कुशवाहा, हेमंत तिवारी, राजीव सिंह, इरफान सिद्दीकी, दुर्गेश गुप्ता, संजीव मंदिलवार, संध्या रवानी, सीमा सोनी, संजय सिंह, शैलेंद्र सोनी, आर.डी.एस. चौहान, राशिद अहमद, अनिल सिंह 'कर्नल', अशफाक अली, जमील खान, जीवन यादव, आलोक सिंह, मोहम्मद हसन, गीता प्रजापति, रूही गजाला, मेधा खांडेकर, मालती सिंह, चंद्रप्रकाश सिंह, रजनीश सिंह, सोहन जायसवाल, सतीश बारी, निकी खान, सौरभ फिलिप, प्रमोद चौधरी, अमित तिवारी 'राजा', मोहम्मद इमरान, हिमांशु जायसवाल, आलोक गुप्ता, अविनाश कुमार, अमित सिंह, दिनेश शर्मा, रोशन कन्नौजिया, अमित वर्मा, पवन पांडे, विकास शर्मा, विकास केशरी, लखन मरावी, बैजनाथ ठाकुर, परवेज आलम गांधी, तरणराज बाबरा, जमशेर आलम, राहुल सोनी, संजर नवाज, आयुष कुमार, चंचला सांडिल्य, हमीदा बानो, ममता सिंह, अंजू सिंह, हामिदा बानो सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

आफत के साथ राहत की बारिश : उफनाई हसदो,धान रोपाई से खेतों में लौटी रौनक

मूसलाधार बारिश से हसदो उफान पर,किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान....

बारिश बनी राहत भी, आफत भी, नदी-नाले उफान पर, खेतों में तेज हुई धान रोपाई

- उफनाई हसदो,थमा यातायात, झमाझम बारिश से खरीफ खेती को मिली नई जान
- कटगोड़ी-नगर मार्ग घंटों बंद,अच्छी बारिश से धान रोपाई ने पकड़ी रफ्तार
- बरसात का दोहरा असर सड़कें डूबीं, खेत हुए लबालब, किसानों में लौटी उम्मीद
- हसदो नदी उफान पर, खेतों में हरियाली की उम्मीद,बारिश ने बदली सोनहत की तस्वीर
- झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित, लेकिन किसानों के लिए बनी खुशियों की सौगात
- दो दिनों में 97 मिमी बारिश से नदी-नाले उफान पर,किसानों में बढ़ी उम्मीद, कृषि मजदूरों की मांग बढ़ने से मजदूरी पहुंची 400 प्रतिदिन

राजन पाण्डेय

सोनहत/कोरिया,22 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सोनहत विकासखंड सहित आसपास के वनांचल क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश अपने साथ राहत और आफत दोनों लेकर आई है, एक ओर तेज बारिश से हसदो नदी सहित क्षेत्र के अधिकांश नदी-नाले उफान पर आ गए,कई संपर्क मार्ग घंटों बाधित रहे और जनजीवन प्रभावित हुआ,वहीं दूसरी ओर लंबे इंतजार के बाद हुई इस झमाझम वर्षा ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। खेत पानी से लबालब भर गए हैं और पूरे अंचल में धान रोपाई का कार्य तेजी से शुरू हो गया है,लगातार कई घंटों तक हुई बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों का पानी तेजी से निचले इलाकों में पहुंचा,हसदो नदी का जलस्तर बढ़ गया और कई रपटे,पुल-पुलिया तथा नाले पानी में डूब गए,कई स्थानों पर पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा,जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा,इसके बावजूद किसानों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है,क्योंकि समय पर मिले पानी से खरीफ फसलों की बेहतर पैदावार की उम्मीद मजबूत हुई है। खेतों में लौटी रौनक,धान रोपाई तेज-बारिश के बाद पूरे सोनहत क्षेत्र का ग्रामीण परिदृश्य बदल गया है,कुछ दिन पहले तक

सूखे पड़े खेत अब पानी से भर चुके हैं,किसानों ने ट्रैक्टरों के माध्यम से मझाई और खेत तैयार करने का काम तेज कर दिया है। जिन किसानों ने पहले से धान की नर्सरी तैयार कर रखी थी,उन्होंने रोपाई शुरू कर दी है,जबकि अन्य किसान भी तेजी से खेत तैयार करने में जुटे हैं,गांवों में सुबह से शाम तक महिलाएं और पुरुष खेतों में धान रोपाई करते दिखाई दे रहे हैं,कई स्थानों पर पारंपरिक सामूहिक श्रमदान के माध्यम से भी रोपाई का कार्य किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में भी नियमित वर्षा होती रही तो इस वर्ष धान की अच्छी पैदावार की पूरी संभावना है।

कटगोड़ी-नगर मार्ग घंटों रहा बंद- भारी बारिश का असर सड़क यातायात पर भी देखने को मिला,कटगोड़ी से नगर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित नाले में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि सड़क के ऊपर से पानी बहने लगा,इसके चलते यह मार्ग कई घंटों तक पूरी तरह बंद रहा,मार्ग अवरुद्ध होने से दैनिक यात्रियों, मरीजों और जरूरी कार्यों से आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई,कई वाहन दोनों ओर खड़े होकर पानी कम होने का इंतजार करते रहे,जलस्तर घटने के बाद ही आवागमन सामान्य हो सका।

प्रशासन ने जारी की सतर्कता की अपील- लगातार बारिश और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है,प्रशासन ने उफनते नदी-नालों,रपटों और पुल-पुलियों को पार नहीं करने,जलप्रपातों के किनारे अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने तथा बच्चों को जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रखने की सलाह दी है,साथ ही मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रशासन को सूचना देने का आग्रह किया गया है।

कृषि मजदूरों की बढ़ी मांग,मजदूरी पहुंची 400 प्रतिदिन

एक साथ पूरे क्षेत्र में धान रोपाई शुरू होने से कृषि मजदूरों की मांग भी अचानक बढ़ गई है, मजदूरों की कमी के कारण कई गांवों में दैनिक मजदूरी बढ़कर लगभग 400 रुपये प्रतिदिन तक पहुंच गई है,किसान समय पर रोपाई पूरी करने के लिए मजदूरों की तलाश कर रहे हैं,स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष बारिश के शुरुआती दौर में मजदूरों की मांग बढ़ती है,लेकिन इस बार एक साथ अच्छी बारिश होने से लगभग सभी गांवों में रोपाई शुरू हो गई है। इससे मजदूरों को भी बेहतर रोजगार और अधिक आय मिलने लगी है।

उफान पर हसदो नदी,जलप्रपातों का बदला स्वरूप

लगातार बारिश के कारण क्षेत्र की जीवनदायिनी हसदो नदी पूरे वेग से बह रही है,नदी के साथ-साथ कई छोटे-बड़े नाले भी उफान पर हैं, कई रपटे और एनीकट पानी में डूब गए हैं, जिससे ग्रामीणों को सतर्क रहने की जरूरत पड़ रही है,वहीं गौर घाट और प्रसिद्ध अमृतधारा जलप्रपात का नजारा भी पूरी तरह बदल गया है,पहाड़ियों से गिरती दूधिया जलधारा और चारों ओर फैली हरियाली प्राकृतिक सौंदर्य को और आकर्षक बना रही है,हालांकि तेज बहाव को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण पर्यटकों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं।

दो दिनों में 97 मिमी बारिश, फिर भी पिछले वर्ष से पीछे- प्राप्त वर्षा आंकड़ों के अनुसार, 21 जुलाई को 20 मिमी तथा 22 जुलाई को 77 मिमी वर्षा दर्ज की गई, यानी केवल दो दिनों में कुल 97 मिमी बारिश हुई, इसी बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया और धान रोपाई का कार्य तेज हो गया, हालांकि पूरे मानसून सत्र की बात करें तो अब तक 289 मिमी वर्षा दर्ज की गई है,जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक 513 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी,यानी इस वर्ष अब तक 224 मिमी कम बारिश हुई है,बावजूद इसके हालिया अच्छी वर्षा ने किसानों में नई उम्मीद जगा दी है,अब उनकी नजर आने वाले दिनों की नियमित और संतुलित बारिश पर टिकी है,ताकि खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार सुनिश्चित हो सके।

जुताई विवाद में पिता पर टांगी और लाठी से हमला,तीन आरोपी गिरफ्तार

राजपुर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त टांगी व डंडा किया जब्त,आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा

राजन पाण्डेय

राजपुर,22 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुढ़ाबगीचा में बाड़ी की जुताई को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति पर टांगी और लाठी से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, प्रार्थी प्रवीण रावत ने 22 जुलाई 2026 को राजपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सुबह करीब 6:30 बजे ट्रैक्टर से अपनी बाड़ी की जुताई कर रहा था। इसी दौरान उसकी मौसी कमलपति सार्थी ने जुताई करने से मना किया। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि कुछ देर बाद सुखसागर उर्फ कमाडो सार्थी, कुरलू उर्फ रमेश सार्थी एवं कमलपति सार्थी डंडा और टांगी लेकर पहुंचे तथा प्रार्थी के पिता देवराज, माता श्यामपति तथा भाइयों राम और अनुराग के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। मारपीट के दौरान देवराज के सिर पर टांगी से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। प्रकरण में थाना राजपुर पुलिस ने अपराध क्रमांक 195/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 351(2), 115(2), 109(1) एवं 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त टांगी एवं डंडा जब्त किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 22 जुलाई 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय, बलरामपुर में पेश किया। मामले के अन्य पहलुओं की विवेचना जारी है।

सीबीएसई ईस्ट ज़ोन ताइक्वांडो प्रतियोगिता में माउंट लिटरा के शौर्यवर्धन सिंह ने जीता स्वर्ण पदक

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,22 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आयोजित सीबीएसई ईस्ट ज़ोन ताइक्वांडो प्रतियोगिता में माउंट लिटरा स्कूल के छात्र शौर्यवर्धन सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शौर्यवर्धन की इस शानदार सफलता के आधार पर उनका चयन अब सीबीएसई नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए किया गया है। यह उपलब्धि न केवल उनके लिए, बल्कि माउंट लिटरा स्कूल, उनके परिवार और पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। शौर्यवर्धन की इस सफलता पर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों, सहपाठियों एवं उनके शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें नेशनल प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सभी ने विश्वास जताया कि वे राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे।

ग्रामीण के घर से नकदी व मंगलसूत्र चोरी

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,22 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

मणिपुर थाना अंतर्गत परिवार के साथ रोपा लगाने के लिए गए ग्रामीण के घर से नकद रकम और मंगलसूत्र चोरी करने का मामला सामने आया है। ग्राम केशवपुर बरपारा निवासी दुलेश्वर ने बताया है कि 19 जुलाई को सुबह 10 बजे परिवार के लोग खेत में रोपा लगाने गये थे। शाम 4 बजे वापस आए तो देखा कि घर का दरवाजा-कुंडी टूटा हुआ है। अंदर जाने पर अलमारी खुला मिली और अंदर रखा 20 हजार रुपये नकद और लगभग 10 हजार रुपये का सोने का मंगलसूत्र चोरी करके ले गए। मणिपुर थाना पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

करंट की चपेट में आने से युवक की मौत

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,22 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

करंट की चपेट में आए युवक की अस्पताल लाते तक मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, मणीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुन्दरपुर का अनुक धोबिया पिता शोभन राम 44 वर्ष, मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे दरवाजे के पास खड़ा होकर बिजली का तार जोड़ रहा था। इसी दौरान लगे करंट के झटका लगने से दरवाजे पर ही गिर गया था। पुत्र को करंट का झटका खाकर गिरते मां गिरहुल बाई ने देखा और शोर मचाकर इसकी जानकारी परिवार के सदस्यों को दी। शोर सुनकर मौके पर पुत्र शिवकुमार पहुंचा और बिजली बंद करके अपने पिता को उठाया। परिजन उसे बेहोशी की हालत में मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां आपातकालीन चिकित्सा परिसर के जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

पुलिस सैलरी पैकेज के तहत दिवंगत प्रधान आरक्षक की पत्नी को 10 लाख रुपये का बीमा चेक प्रदान

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,22 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत दिवंगत प्रधान आरक्षक (एमटी) पुरुषोत्तम पैकरा की पत्नी श्रीमती जगरमती पैकरा को 10 लाख रुपये की बीमा राशि का चेक प्रदान किया गया। जानकारी के अनुसार, सरगुजा पुलिस में पदस्थ प्रधान आरक्षक (एमटी) पुरुषोत्तम पैकरा का 7 जनवरी 2026 को आकस्मिक निधन हो गया था। उनके निधन के उपरांत पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत बीमा दावा स्वीकृत होने पर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) तथा भारतीय स्टेट बैंक, अंबिकापुर के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रतीक अग्निहोत्री ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनकी पत्नी श्रीमती जगरमती पैकरा को 10 लाख रुपये का चेक सौंपा। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के प्रबंधक शिरीष गीर, मुख्य शाखा अधिकारी आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थापना शाखा के उपनिरीक्षक (एम) अभय सिंह सहित पुलिस विभाग एवं बैंक के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

थाने से 500 मीटर दूर 70 लाख की मोबाइल चोरी,शटर तोड़कर सीसीटीवी भी किया ध्वस्त

बगीचा बस स्टैंड स्थित कैपिटल मोबाइल दुकान में देर रात वारदात,व्यापारियों में आक्रोश

-संवाददाता-

जशपुर/बगीचा,22 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

जशपुर जिले के बगीचा बस स्टैंड स्थित कैपिटल मोबाइल दुकान में मंगलवार देर रात हुई बड़ी चोरी की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। हैरानी की बात यह है कि घटना स्थल बगीचा थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद बेखौफ चोर दुकान का शटर तोड़कर करीब 60 से 70 लाख रुपये मूल्य के मोबाइल फोन चोरी कर ले गए और फरार हो गए। दुकान संचालक सबा के अनुसार, चोर बड़ी तैयारी के साथ आए थे। वारदात को अंजाम

देने के बाद उन्होंने दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, ताकि कोई साक्ष्य न बच सके। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरी की पूरी योजना पहले से बनाई गई थी। घटना के बाद पुलिस की रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। थाना से इतनी कम दूरी पर स्थित दुकान में लाखों रुपये की चोरी होना पुलिस की सतर्कता पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि थाना के आसपास ही व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं, तो दूर-दराज के क्षेत्रों की सुरक्षा का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

इस वारदात के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने, बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा चोरी में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

तालाब तो बह गया...अब जवाबदेही भी बहेगी या तय होगी? सोनहत वन विभाग के निर्माण पर उठे बड़े सवाल

पहली ही बारिश में ढहा जल संरक्षण का दावा,गुणवत्ता,निगरानी और सरकारी धन के उपयोग पर उठे गंभीर प्रश्न

कोरिया वन मंडल में संरक्षण पीछे, निर्माण आगे?

चंदन चोरी से 'कागजी तालाब' तक लगातार उठते सवाल,पहली ही बारिश में बहा तालाब तो विभागीय कार्यप्रणाली कठघरे में...आखिर जिम्मेदारी किसकी?

दैनिक घटती-घटना की सिलसिलेवार खबरों ने खोली वन विभाग की कई परतें, अब जनता पूछ रही—क्या जंगल, वन्यजीव और वन संपदा की सुरक्षा से ज्यादा प्राथमिकता निर्माण कार्यों को?

-राजन पाण्डेय-

सोनहत/कोरिया,22 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

जल संरक्षण के उद्देश्य से सरकारी धन से तैयार किए गए तालाब का पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो जाना अब केवल एक निर्माण कार्य की विफलता का मामला नहीं रह गया है, इस घटना ने वन विभाग की कार्यप्रणाली,निर्माण गुणवत्ता,तकनीकी निगरानी और जवाबदेही को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सार्वजनिक धन से बनाए गए निर्माण पहली ही बारिश नहीं झेल पाते, तो स्वाभाविक रूप से पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है, इस मामले को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 17 जुलाई को दैनिक घटती-घटना ने 'कागजों में बने तालाब, जमीन पर गड्ढे!' शीर्षक से निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं, गुणवत्ता पर सवाल और मशीनों के उपयोग सहित कई मुद्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, स्थानीय लोगों का कहना है कि खबर प्रकाशित होने के बाद उसी रात हुई बारिश में संबंधित तालाब की मेड़ टूट गई और निर्माण की वास्तविक स्थिति सामने आ गई, इसके बाद पहले लगाए जा रहे आरोपों और सवालों को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। बता दे की वन विभाग का मूल दायित्व जंगलों की सुरक्षा,वन्यजीवों का संरक्षण, पौधों एवं वृक्षों की रक्षा,अवैध कटाई और तस्करी पर रोक तथा प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन है,सरकार हर वर्ष वन संरक्षण, जैव विविधता,जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है,लेकिन यदि किसी वन मंडल में बार-बार ऐसे मामले सामने आने लगें,जिनमें कभी सरकारी नर्सरी से बेशकीमती चंदन के पेड़ गायब हो जाएं, कभी जल संरक्षण के नाम पर बने तालाब पहली ही बारिश में बह जाएं,कभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर आरोप लगें और विभागीय जवाबदेही स्पष्ट न हो,तो स्वाभाविक रूप से पूरे तंत्र पर सवाल उठना लाजिमी है, कोरिया वन मंडल में बीते कुछ महीनों के दौरान सामने आए घटनाक्रमों ने यही तस्वीर प्रस्तुत की है, दैनिक घटती-घटना ने सिलसिलेवार प्रकाशित अपनी खबरों के माध्यम से कई ऐसे मुद्दों को सामने रखा,जिन्होंने वन विभाग की कार्यशैली,निर्माण कार्यों की गुणवत्ता,तकनीकी निगरानी,पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर बहस छेड़ दी है।

निरीक्षण व्यवस्था पर भी उठे सवाल- सरकारी निर्माण कार्यों में योजना स्वीकृति से लेकर अंतिम भुगतान तक कई स्तरों पर निरीक्षण और गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था रहती है, ऐसे में यदि निर्माण पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है कि क्या निर्माण के दौरान नियमित निरीक्षण हुआ? क्या तकनीकी अधिकारियों ने स्थल का भौतिक सत्यापन किया? क्या माप पुस्तिका और गुणवत्ता परीक्षण के आधार पर भुगतान किया गया? यदि सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार पूरी हुई थीं तो फिर निर्माण इतनी जल्दी क्यों क्षतिग्रस्त हुआ?

पारदर्शिता को लेकर भी उठ रहे प्रश्न- स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल पर योजना से संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं थी,आमतौर पर ऐसे कार्यों में योजना का नाम,स्वीकृत राशि,निर्माण एजेंसी, कार्य अवधि और संबंधित अधिकारियों की जानकारी प्रदर्शित करने का प्रावधान रहता है, यदि यह जानकारी उपलब्ध नहीं थी तो इससे पारदर्शिता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

मशीनों के उपयोग को लेकर भी चर्चा- ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में स्थानीय मजदूरों की अपेक्षा मशीनों का अधिक उपयोग किया गया,यदि जांच में यह तथ्य सही पाया जाता है तो यह भी देखा जाना आवश्यक होगा कि कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों और स्वीकृत प्रक्रिया के अनुरूप हुआ था या नहीं, यह पहलू इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना भी माना जाता है।

क्या खबर ने पोल खोली या महज संयोग था?- तालाब बहने के बाद पूरे क्षेत्र में एक ही चर्चा होने लगी क्या दैनिक घटती-घटना द्वारा उठाए गए सवाल सही साबित हुए? या यह केवल प्राकृतिक कारणों से हुआ हादसा था? यद्यपि इसका अंतिम निष्कर्ष किसी सक्षम जांच से ही निकल सकता है, लेकिन तालाब बहने के बाद निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल और तेज हो गए।

पुराने मामलों की भी होने लगी चर्चा- तालाब बहने के बाद लोगों ने वन विभाग से जुड़े पुराने मामलों को भी जोड़ना शुरू कर दिया,ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि क्या जंगलों में लगी भीषण आग के मामलों में क्या कार्रवाई हुई? चंदन चोरी के दोषी कौन हैं? क्या निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की कभी स्वतंत्र जांच हुई? क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय हुई? इन सवालों ने पूरे विभाग की कार्यशैली पर व्यापक चर्चा शुरू कर दी है।

सरकारी योजनाएं केवल निर्माण नहीं,जनता के विश्वास की भी परियोजना होती हैं- सरकारी योजनाओं का उद्देश्य केवल बजट खर्च करना नहीं होता,इनका उद्देश्य जनता का विश्वास मजबूत करना,प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और सार्वजनिक हित सुनिश्चित करना होता है,यदि करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी निर्माण पहली बारिश में बह जाए, सरकारी नर्सरी से चंदन गायब हो जाए और लगातार सवाल उठते रहें,तो यह केवल एक विभाग का मामला नहीं रह जाता, बल्कि शासन की जवाबदेही का विषय बन जाता है।

अब निगाहें जांच और जवाबदेही पर- दैनिक घटती-घटना द्वारा लगातार प्रकाशित खबरों ने जिन सवालों को उठाया,वे अब सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं, हालांकि किसी भी अनियमितता या जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण सक्षम जांच और आधिकारिक निष्कर्षों के आधार पर ही होगा। लेकिन यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि यदि निर्माण गुणवत्ता,तकनीकी प्रक्रिया या विभागीय निगरानी में किसी स्तर पर कमी पाई जाती है, तो जिम्मेदारी केवल कागजों तक सीमित न रहे, अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है क्या इस बार केवल बह चुके तालाब की मरम्मत होगी, या फिर उस व्यवस्था की भी,जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं? क्या चंदन चोरी से लेकर तालाब निर्माण तक के मामलों में जवाबदेही तय होगी,या ये मुद्दे भी समय के साथ फाइलों में दब जाएंगे? कोरिया वन मंडल से जुड़े इन घटनाक्रमों ने इतना तो स्पष्ट कर दिया है कि जनता अब केवल निर्माण नहीं,बल्कि पारदर्शिता,गुणवत्ता और जवाबदेही भी चाहती है,अब यह विभाग और शासन पर निर्भर करेगा कि वह इन सवालों का उत्तर तथ्यों, जांच और कार्रवाई के माध्यम से देता है या नहीं।

जल संरक्षण की योजना या सरकारी धन की औपचारिकता?

सरकार हर वर्ष जल संरक्षण,भू-जल स्तर बढ़ाने और वन्यजीवों के लिए जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये की योजनाएं संचालित करती है,इन योजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कराना नहीं, बल्कि लंबे समय तक उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना होता है,लेकिन सोनहत वन परिक्षेत्र में निर्मित तालाब के पहली ही बारिश में बह जाने की घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या योजना का क्रियान्वयन निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप हुआ था या केवल कार्य पूर्ण दिखाकर सरकारी राशि खर्च कर दी गई।

पहली बारिश ने खोल दी निर्माण की हकीकत

स्थानीय लोगों के अनुसार तालाब का निर्माण पूरा होने के कुछ समय बाद ही हुई शुरुआती बारिश में उसकी मेड़ टूट गई और संरचना क्षतिग्रस्त हो गई,ग्रामीणों का कहना है कि यदि निर्माण मजबूत और निर्धारित मानकों के अनुरूप होता तो सामान्य बारिश में इस प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए था,यदि यह स्थिति सही है तो स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न उठते हैं क्या मिट्टी का पर्याप्त संपीड़न किया गया था? क्या मेड़ की चौड़ाई और ऊंचाई तकनीकी मानकों के अनुरूप थी? क्या अतिरिक्त पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी? क्या निर्माण के दौरान गुणवत्ता परीक्षण किया गया? इन सवालों के जवाब अब केवल विभागीय दावों से नहीं बल्कि तकनीकी जांच से ही सामने आ सकते हैं।

सबसे बड़ा सवाल-जिम्मेदारी किसकी होगी?

सरकारी निर्माण किसी एक कर्मचारी के भरोसे नहीं होता। योजना स्वीकृति,तकनीकी डिजाइन, कार्य निष्पादन, निरीक्षण, माप पुस्तिका, गुणवत्ता परीक्षण और भुगतान जैसी प्रत्येक प्रक्रिया में अलग-अलग स्तर पर अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं,ऐसे में यदि निर्माण कार्य शुरुआती बारिश में ही क्षतिग्रस्त हो जाता है तो केवल निर्माण एजेंसी ही नहीं,बल्कि पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया की भी समीक्षा आवश्यक हो जाती है, क्या निर्माण गुणवत्ता के अनुरूप हुआ था? क्या तकनीकी निरीक्षण वास्तव में किया गया? क्या भुगतान से पहले गुणवत्ता परीक्षण हुआ? क्या जिम्मेदारी केवल निचले स्तर तक सीमित रहेगी या पूरी प्रशासनिक श्रृंखला की जांच होगी?

चंदन चोरी ने पहली बार हिलाई थी व्यवस्था

मामलों की शुरुआत उस समय हुई जब सोनहत स्थित शासकीय नर्सरी से बेशकीमती चंदन के पेड़ों के गायब होने का मामला सामने आया,यह कोई सामान्य चोरी नहीं थी, जिस नर्सरी को वन विभाग की सबसे सुरक्षित परिसंपत्तियों में गिना जाता है,वहीं से वर्षों पुराने चंदन के वृक्ष गायब हो गए,यह घटना केवल चोरी तक सीमित नहीं रही। इसने सुरक्षा व्यवस्था पर कई प्रश्न खड़े कर दिए,यदि विभाग अपने मुख्यालय की नर्सरी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है,तो हजारों हेक्टेयर जंगलों की सुरक्षा का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? दैनिक घटती-घटना ने इस मामले को लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया। समाचारों में यह प्रश्न भी उठाया गया कि चोरी के बाद क्या एफआईआर दर्ज हुई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हुई? क्या किसी कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई हुई? क्या चोरी की निष्पक्ष जांच पूरी हुई? इन सवालों के सार्वजनिक उत्तर आज तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सके।

जनविश्वास का भी है सवाल

सरकारी परियोजनाएं केवल निर्माण कार्य नहीं होतीं,बल्कि वे जनता के विश्वास का भी प्रतीक होती हैं,यदि सार्वजनिक धन से बनी संरचनाएं पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो जाएं तो इससे योजनाओं की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है, अब देखना यह होगा कि सोनहत का यह मामला भी केवल मरम्मत तक सीमित रहता है या फिर निर्माण की गुणवत्ता, तकनीकी परीक्षण,प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक धन के उपयोग की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक जिम्मेदारी तय की जाती है, फिलहाल जनता का सबसे बड़ा सवाल यही है क्या इस बार केवल तालाब की मरम्मत होगी, या फिर उस व्यवस्था की भी, जिसने पहली ही बारिश में उसे बह जाने दिया?

CMYK

असुरक्षित भवन में पढ़ने को मजबूर मासूम ! पोड़ीडीह में एक साल से अधूरा स्कूल मरम्मत कार्य,जर्जर आंगनबाड़ी में चल रही कक्षाएं...

महिला एवं बाल विकास विभाग जिस भवन को घोषित कर चुका असुरक्षित,उसी में शिक्षा विभाग करा रहा पढ़ाई;जनपद सीईओ बोले...दो नोटिस दे चुके हैं,अब होगी आगे की कार्रवाई

राजेन्द्र शर्मा

खड़गवां,22 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। एमसीबी जिले के खड़गवां विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पोड़ीडीह में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी गंभीर लापरवाही सामने आई है,यहां प्राथमिक शाला भवन के मरम्मत कार्य को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है,लेकिन आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया,इसका खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बच्चे ऐसे जर्जर आंगनबाड़ी भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं,जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग पहले ही असुरक्षित मानते हुए खाली करा चुका था,सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिस भवन में बच्चों की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं,उसकी छत से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, कई स्थानों पर लोहे की सरिया बाहर दिखाई दे रही हैं और भवन की हालत किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है,इसके बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा उसी भवन में प्राथमिक शाला की कक्षाएं संचालित कराई जा रही हैं।

असुरक्षित घोषित भवन में पढ़ाई,आखिर जिम्मेदार कौन?

स्थानीय लोगों के अनुसार जिस भवन को महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी संचालन के लिए असुरक्षित मानते हुए खाली करा दिया था,उसी भवन में अब प्राथमिक शाला के बच्चों को बैठाया जा रहा है,यदि यह तथ्य सही है तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं जब आंगनबाड़ी के लिए भवन असुरक्षित था तो प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए कैसे सुरक्षित हो गया? क्या भवन की कोई तकनीकी सुरक्षा जांच कराई गई? क्या किसी सक्षम अधिकारी से इस भवन में कक्षाएं संचालित करने की अनुमति ली गई? यदि सुरक्षा परीक्षण नहीं हुआ तो बच्चों को वहां बैठाने का निर्णय किस आधार पर लिया गया? इन सवालों का जवाब संबंधित विभागों को देना होगा।

छत से झड़ रहा प्लास्टर,बाहर निकली सरिया

मौके पर भवन की स्थिति देखने पर स्पष्ट होता है कि भवन काफी पुराना और जर्जर हो चुका है, छत और दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा है तथा कई स्थानों पर सरिया बाहर दिखाई दे रही है, विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे भवनों में लगातार बच्चों की मौजूदगी जोखिम भरी हो सकती है,बरसात के मौसम में इस प्रकार के भवनों में दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है।

एक साल से अधूरा पड़ा मरम्मत कार्य- जानकारी के अनुसार प्राथमिक शाला भवन के मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी लगभग एक वर्ष पहले ग्राम पंचायत पोड़ीडीह को निर्माण एजेंसी के रूप में सौंपी गई थी,निर्धारित समय में कार्य पूरा होना था,लेकिन आज तक भवन पूरी तरह तैयार नहीं हो सका,नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है,लेकिन बच्चे अब भी अपने मूल विद्यालय में नहीं लौट पाए हैं,परिसर में निर्माण सामग्री बिखरी हुई दिखाई देती है और कार्य लगभग ठप नजर आता है,इससे निर्माण कार्य की गति और निगरानी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं।

निर्माण एजेंसी पर क्या हुई कार्रवाई?

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माण एजेंसी समय पर कार्य पूरा नहीं कर सकी तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए,लोगों का सवाल है क्या निर्माण एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया? क्या विलंब के लिए आर्थिक दंड लगाया गया? क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय की गई? यदि नहीं,तो इससे निर्माण कार्यों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

दुर्घटना हुई तो जिम्मेदार कौन होगा?

सबसे बड़ा सवाल बच्चों की सुरक्षा को लेकर है, यदि भविष्य में इस जर्जर भवन में कोई दुर्घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या इसकी जवाबदेही शिक्षा विभाग की होगी, निर्माण एजेंसी की, ग्राम पंचायत की या फिर जनपद पंचायत की? इन सवालों का जवाब प्रशासन को स्पष्ट करना होगा।

जनपद पंचायत की निगरानी पर भी सवाल- निर्माण कार्य में लगातार हो रही देरी के कारण अब जनपद पंचायत खड़गवां की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करना और समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा कराना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है,ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि निर्माण एजेंसी निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं कर सकी तो उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई? क्या कारण है कि एक वर्ष बाद भी बच्चे अपने विद्यालय में नहीं लौट पाए?

सीईओ बोले...दो नोटिस जारी किए जा चुके हैं- इस संबंध में जब जनपद पंचायत खड़गवां के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) रूपेश कुमार बंजारे से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि निर्माण एजेंसी को अब तक दो नोटिस जारी किए जा चुके हैं,उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो संबंधित उच्च अधिकारियों को जानकारी भेजकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी,हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा और बच्चों को सुरक्षित भवन कब उपलब्ध कराया जाएगा।

अब प्रशासनिक हस्तक्षेप की जरूरत- पोड़ीडीह का यह मामला केवल निर्माण कार्य में देरी का नहीं, बल्कि मासूम बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है,ऐसे में आवश्यक है कि प्रशासन तत्काल भवन की तकनीकी जांच कराए,यदि भवन असुरक्षित है तो बच्चों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा अधूरे निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कराए,क्योंकि शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक होगा,जब बच्चों को सुरक्षित वातावरण में पढ़ने का अवसर मिले,आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है,या उससे पहले जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी?

जंतर-मंतर घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो,दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई : सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र,छात्रों और महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार,सादे कपड़ों में कार्रवाई करने वालों की पहचान सार्वजनिक करने की मांग

-संवाददाता-

मनेंद्रगढ़,22 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने दिल्ली के जंतर-मंतर में 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों एवं महिलाओं के साथ कथित पुलिस कार्रवाई को गंभीर बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है,उन्होंने पूरे घटनाक्रम की तत्काल,निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सांसद महंत ने कहा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वीडियो और दृश्य सामग्री में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निहत्थे नागरिकों, विशेषकर छात्रों और युवाओं,के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार दिखाई दे रहा है,उन्होंने विशेष चिंता महिलाओं एवं छात्राओं के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार को लेकर जताई,

उनके अनुसार वायरल वीडियो में कुछ वर्दीधारी पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ बल प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं,जबकि घटना के बाद कुछ अधिकारियों के हंसते हुए दिखाई देने के दृश्य भी सामने आए हैं,जो पुलिस की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं, सांसद महंत ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे,जिनके पास न तो कोई पहचान-पत्र था और न ही उनकी आधिकारिक पहचान स्पष्ट थी, लेकिन वे हाथों में डंडे लेकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते दिखाई दिए,उन्होंने कहा कि बिना स्पष्ट पहचान वाले व्यक्तियों की भीड़ नियंत्रण में भूमिका की निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से कुछ नागरिक इन व्यक्तियों की पहचान करने का दावा कर रहे हैं तथा कुछ नाम भी सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। ऐसे में आधिकारिक जांच और स्पष्ट तथ्य सामने लाना जरूरी है,ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे,सांसद ने गृह मंत्रालय से मांग की है कि महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान कर उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए।

एमसीबी में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल : अव्यवस्था,मनमानी और प्रशासनिक शिथिलता के आरोपों से घिरा शिक्षा विभाग

सूत्रों के हवाले से सामने आईं कई गंभीर जानकारियां,प्रशिक्षण,स्कूल प्रबंधन और विभागीय कार्यशैली पर उठे सवाल

मनेंद्रगढ़,22 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। एमसीबी जिले की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर विभागीय कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में शिक्षा विभाग प्रशासनिक शिथिलता,समन्वय की कमी और कथित मनमानी के दौर से गुजर रहा है,शिक्षकों के प्रशिक्षण में देरी, विद्यालयों की जर्जर स्थिति,डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था के दुरुपयोग,विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न प्रशासनिक मामलों में लापरवाही को लेकर विभाग के भीतर और बाहर असंतोष की स्थिति बताई जा रही है,यदि सूत्रों के दावों में तथ्य हैं, तो इसका सीधा प्रभाव जिले के हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई,शिक्षकों की कार्यक्षमता और सरकारी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है,हालांकि इन सभी बिंदुओं पर विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी शेष है।

नई पुस्तकें लागू,लेकिन माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं- सूत्रों के अनुसार,जिले के माध्यमिक विद्यालयों में नए पाठ्यक्रम और नई पुस्तकों के अनुसार शिक्षण कार्य प्रारंभ करा दिया गया है, लेकिन अधिकांश शिक्षकों को अब तक आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया है,बताया जा रहा है कि बिना प्रशिक्षण के शिक्षकों को नई विषयवस्तु समझने और विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने में कठिनाई हो रही है,शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी नए पाठ्यक्रम को लागू करने से पहले शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य होता है,ताकि शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित न हो।

जिला शिक्षा अधिकारी की नियमित उपस्थिति को लेकर सवाल- विभागीय सूत्रों का दावा है कि जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में नियमित रूप से उपलब्ध नहीं रहने के कारण अनेक प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं,बताया जा रहा है कि अधिकारी सप्ताह के सीमित दिनों में ही कार्यालय में बैठते हैं,जिससे दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले शिक्षक,कर्मचारी और आम नागरिकों को कई बार बिना काम कराए लौटना पड़ता है,यदि ऐसा है,तो इससे विभागीय फाइलों के निस्तारण और जनसमस्याओं के समाधान में अनावश्यक विलंब होना स्वाभाविक माना जा रहा है।

वीएसके ऐप की ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था पर भी उठे सवाल- सूत्रों के मुताबिक, विभाग के कुछ कर्मचारी विद्यालयों में विद्या समीक्षा केंद्र ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज तो कर देते हैं,लेकिन वास्तविक रूप से विद्यालयों में उपस्थित न होकर दिनभर कार्यालयों में समय बिताते हैं,यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं,तो इससे स्पष्ट होगा कि डिजिटल उपस्थिति प्रणाली का उद्देश्य ही प्रभावित हो रहा है,इससे विद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

'नेक्स्ट टू डीईओ' बताकर प्रभाव बनाने की चर्चा- विभाग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग का एक अधीनस्थ अधिकारी स्वयं को 'नेक्स्ट टू डीईओ' बताकर प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहा है,कार्यालयीन गलियारों में इस प्रकार की चर्चाओं ने कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच भ्रम और असहजता का माहौल पैदा कर दिया है, सूत्रों का कहना है कि यदि विभागीय अधिकारों और जिम्मेदारियों की स्पष्टता नहीं रहेगी तो प्रशासनिक अनुशासन भी प्रभावित हो सकता है।

बीच सत्र में 50 विद्यार्थियों के नाम काटे जाने का मामला अब भी लंबित

सूत्रों के अनुसार,जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में प्रधान पाठक द्वारा शैक्षणिक सत्र के दौरान लगभग 50 विद्यार्थियों के नाम विद्यालय से काट दिए जाने का मामला अब तक लंबित है, बताया जा रहा है कि मामला विभाग के संज्ञान में आने के बावजूद अब तक जांच प्रारंभ नहीं हो सकी है,यदि यह तथ्य सही हैं,तो इससे प्रभावित विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनके शैक्षणिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

उठ रहे हैं कई अहम सवाल

- नई पुस्तकें लागू होने के बाद भी शिक्षकों को समय पर प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया गया?
- यदि अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं तो प्रशासनिक कार्यों की निगरानी कौन कर रहा है?
- क्या वीएसके ऐप की उपस्थिति व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है?
- जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत में देरी क्यों हो रही है?
- राज्यपाल पुरस्कार प्रक्रिया को लेकर उठ रही चर्चाओं की निष्पक्ष जांच होगी या नहीं?
- 50 विद्यार्थियों के नाम काटे जाने के मामले में विभागीय कार्रवाई कब शुरू होगी?

बारिश में जर्जर स्कूल भवन, बच्चों की सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा- मानसून के दौरान जिले के कई शासकीय विद्यालयों की स्थिति अत्यंत खराब बताई जा रही है, सूत्रों के अनुसार अनेक स्कूल भवनों की छतों से पानी टपक रहा है, जबकि कुछ भवन जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं,स्थानीय स्तर पर कई बार लिखित आवेदन और शिकायतें दिए जाने के बावजूद आवश्यक मरम्मत या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने की बात कही जा रही है,यदि यह स्थिति बनी रही तो विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

राज्यपाल पुरस्कार चयन प्रक्रिया पर भी उठे सवाल- सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही कथित रूप से लेन-देन की चर्चाएं शुरू हो गई हैं,इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि ऐसी शिकायतों में तथ्य पाए जाते हैं तो पुरस्कार प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो सकते हैं, ऐसे मामलों में विभागीय स्तर पर पारदर्शी जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

थाने से चंद कदम दूर चोरी,खड़गवां पुलिस की रात्रि गश्त पर उठे गंभीर सवाल

मुख्य बाजार की मोबाइल दुकान में दीवार तोड़कर लाखों के मोबाइल और सामान पर हाथ साफ,व्यापारियों में दहशत,सुरक्षा व्यवस्था पर उठे प्रश्न

राजेन्द्र शर्मा

खड़गवां 22 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। खड़गवां मुख्यालय के बस स्टैंड स्थित मुख्य बाजार में एक मोबाइल दुकान में हुई चोरी की घटना ने पुलिस की रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दुकान में चोरी हुई, वह पुलिस थाने से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है, इसके बावजूद चोर पूरी योजना के साथ दुकान की दीवार तोड़कर अंदर घुसे, मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान समेटकर फरार हो गए और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, घटना ने न केवल व्यापारियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि यदि थाने के नजदीक स्थित मुख्य बाजार ही सुरक्षित नहीं है तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी होगी।

फिल्मी अंदाज में दीवार तोड़कर दिया वारदात को अंजाम- जानकारी के अनुसार चोरों ने दुकान के मुख्य शटर या ताले को तोड़ने के बजाय दीवार में सेंध लगाकर दुकान के भीतर प्रवेश किया, इसके बाद दुकान में रखे मोबाइल फोन और अन्य मूल्यवान सामान लेकर आराम से फरार हो गए, वारदात के तरीके से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों ने पहले से रेकी कर पूरी योजना के साथ घटना को अंजाम दिया, सुबह जब दुकान संचालक प्रतिष्ठान खोलने पहुंचे तो दुकान की दीवार टूटी हुई मिली और अंदर रखा सामान गायब था, इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

थाने के पास ही हुई चोरी, गश्त पर उठे सवाल- इस चोरी की सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि वारदात थाना क्षेत्र के सबसे संवेदनशील और व्यस्त इलाके में हुई, बस स्टैंड और मुख्य बाजार में दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है तथा पुलिस की नियमित गश्त का भी दावा किया जाता है, ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि यदि चोर इतनी आसानी से थाने के नजदीक स्थित दुकान में सेंधमारी कर सकते हैं तो रात्रि गश्त की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

व्यापारियों में बढ़ी असुरक्षा की भावना- घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश और चिंता का माहौल है, उनका कहना है कि लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से व्यापार करना कठिन होता जा रहा है, व्यापारियों का कहना है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में लाखों रुपये का सामान रखते हैं, यदि मुख्य बाजार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो व्यापारियों का भरोसा कमजोर होगा, उनका यह भी कहना है कि पुलिस को केवल घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय अपराध रोकने की दिशा में प्रभावी रणनीति अपनानी चाहिए।

रात्रि गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी निगरानी मजबूत करने की मांग-

व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मुख्य बाजार और बस स्टैंड क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए, संवेदनशील स्थानों पर नियमित पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए, बाजार क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की गंभीरता से जांच की जाए, चोरी की घटना में शामिल आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए।

मुख्यालय सुरक्षित नहीं तो ग्रामीण क्षेत्रों का क्या?-

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पुलिस थाने के समीप स्थित सबसे व्यस्त बाजार में चोरी हो सकती है तो दूर-दराज के गांवों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से सीमित पुलिस उपस्थिति रहती है, ऐसे में मुख्यालय की यह घटना सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

पुलिस के सामने चुनौती-

अब खड़गवां पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है, पहली, इस चोरी का शीघ्र खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करना और चोरी गए सामान की बरामदगी करना, दूसरी, रात्रिकालीन गश्त और निगरानी व्यवस्था को इस प्रकार मजबूत करना कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, फिलहाल व्यापारियों और आम नागरिकों की नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस इस मामले का खुलासा कितनी जल्दी करती है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या ठोस कदम उठाती है।

बारिश में शूट हुआ कल्ट सॉन्ग फिर हुआ रिलीज

90 के दशक के बॉलीवुड के कई गाने आज भी लोगों के दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं। उस दौर के रोमांटिक गानों की बात करें तो कई ऐसे गीत हैं,जिन्हें दर्शक आज भी उतना ही पसंद करते हैं जितना रिलीज के समय करते थे। अब इसी कड़ी में 1998 की फिल्म 'गुलाम' का सुपरहिट रोमांटिक गाना 'आंखों से तूने ये क्या कह दिया' एक बार फिर नए अंदाज में सामने आया है। करीब 28 साल बाद इस कल्ट क्लासिक गाने का रीमेक वर्जन रिलीज किया गया है।

नए गाने का नाम 'आंखों से तूने 2.0' रखा गया है,जिसे फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' के लिए तैयार किया गया है। इस फिल्म में राघव जुयाल और निहारिका एनएम मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। नए वर्जन में दोनों कलाकारों की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। गाने के वीडियो में राघव और निहारिका रोमांटिक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। इस गाने की सबसे खास बात यह है कि इसमें पुराने दौर की यादों को बनाए रखने के लिए ओरिजिनल सिंगर्स की आवाज को भी शामिल किया गया है। नए वर्जन में कुमार सानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज दी है। इसके अलावा देव नेगी और पलक मुच्छल ने भी गाने को अपनी आवाज दी है। गाने को लिजो जॉर्ज ने कंपोज किया है, जबकि इसके नए बोल मोहसिन खान ने लिखे हैं। ओरिजिनल गाना साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म 'गुलाम' का हिस्सा था। फिल्म में आमिर खान और रानी मुखर्जी की जोड़ी नजर आई थी। बारिश में शूट किया गया यह गाना उस समय काफी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसे बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक गानों में गिना जाता है। गाने में आमिर और रानी की शानदार केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। 'आंखों से तूने ये क्या कह दिया' को अलका याग्निक और कुमार सानू ने अपनी आवाज दी थी। इस गाने का संगीत मशहूर संगीतकार जोड़ी जतिन-ललित ने तैयार किया था, जबकि इसके खूबसूरत बोल समीर अंजान ने लिखे थे। गाने की धुन,बोल और बारिश में फिल्माया गया इसका दृश्य आज भी लोगों की पुरानी यादों को ताजा कर देता है। रीमेक वर्जन में भी मेकर्स ने पुराने गाने की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए इसमें ओरिजिनल सिंगर्स की आवाज को बरकरार रखा है। माना जा रहा है कि इससे 90 के दशक के संगीत प्रेमियों को पुराने गाने का एहसास फिर से मिलेगा। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज आज भी करोड़ों लोगों के बीच खास पहचान रखती है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस रीमेक को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई लोगों ने पुराने गाने को याद करते हुए नए वर्जन की तारीफ की है,वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि पुराने क्लासिक गानों को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। उनके अनुसार ओरिजिनल गानों की भावनाएं और लोकप्रियता अलग होती है,जिसे रीमेक में दोहराना आसान नहीं होता। फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' में राघव जुयाल और निहारिका एनएम की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएगी। फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है। यह फिल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब देखना होगा कि 'आंखों से तूने 2.0' दर्शकों के बीच कितना असर छोड़ पाता है और क्या यह पुराने गाने की लोकप्रियता को दोहरा पाता है या नहीं।

3 इडियट्स के री-रिलीज की खबरें अफवाह, विधु विनोद चोपड़ा ने किया साफ़

मशहूर फ़िल्म 3 इडियट्स के मेकर्स ने फ़िल्म के दोबारा रिलीज़ होने की खबरों को गलत बताया है। बुधवार को फ़िल्म के प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया पर साफ़ किया कि फ़ल्मि दोबारा रिलीज़ के लिए सिनेमाघरों में नहीं आ रही है। विधु विनोद चोपड़ा फ़िल्म्स ने 4 सितंबर,2026 को फ़ल्मि के दोबारा रिलीज़ होने की हालिया मीडिया रिपोर्टों के जवाब में एक आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा, हालिया मीडिया रिपोर्टों के संदर्भ में,जिनमें दावा किया गया है कि 3 इडियट्स 4 सितंबर को दोबारा रिलीज़ होगी, विधु विनोद चोपड़ा फ़ल्म्स यह साफ़ करना चाहती है कि ये रिपोर्टें झूठी और तथ्यों के हिसाब से गलत हैं। हम मीडिया के सदस्यों और फ़ैन्स से अनुरोध करते हैं कि वे केवल विधु विनोद चोपड़ा फ़ल्म्स के वेरिफ़ाइड चैनलों के ज़रिए की गई आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें। हम मीडिया प्रकाशनों से आग्रह करते हैं कि वे बिना पुष्टि की गई जानकारी को प्रकाशित या प्रसारित न करें।

ये रिपोर्टें जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान सामने आईं,जब सोनम वांगचुक को 21 दिनों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पूरी करने के बाद 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर विरोध स्थल से ज़बरदस्ती हटा दिया था। यह हड़ताल शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव और पेपर लीक को रोकने के लिए की गई थी। पॉप-कल्चर में,सोनम वांगचुक को अक्सर 3 इडियट्स में आमिर खान के किरदार के पीछे की प्रेरणा माना जाता रहा है। हालाँकि,आमिर ने हाल ही में साफ़ किया कि यह किरदार असल में सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं है,बल्कि लेखकों की कल्पना की उपज है।

3 इडियट्स ने मुख्य रूप से शिक्षा प्रणाली में सुधार और परीक्षा के पेपर से परे ज्ञान के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। यह फ़ल्मि एक मज़बूत सामाजिक संदेश के साथ मुख्यधारा के बॉलीवुड मनोरंजन को नए सिरे से परिभाषित करके भारतीय पॉप-कल्चर में एक मील का पत्थर बन गई। फ़ल्मि ने हास्य और भावनाओं के ज़रिए शैक्षणिक सफलता,माता-पिता के दबाव और करियर के विकल्पों के पारंपरिक विचारों को चुनौती दी। इसने भारत की शिक्षा प्रणाली और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी व्यापक चर्चा को जन्म दिया। इसका प्रभाव सीमाओं से परे रहा, जिससे यह अब तक की सबसे प्रशंसित और विश्व स्तर पर पहचानी जाने वाली हिंदी फ़ल्मिों में से एक बन गई।

50 साल पुराना रीना रॉय का चुलबुला गाना,लता मंगेशकर की आवाज में बना कल्ट क्लासिक

साल 1976 में रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक सुपरहिट फिल्म में साथ काम किया था। इसमें रीना रॉय के चुलबुले अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया था। बॉलीवुड गानों का इमोशन्स के साथ तगड़ा मेल जोल है। यहां आपको हर एक भाव के लिए अलग गाना मिल जाएगा। फिर चाहे वो कोई रोमांटिक गाना हो या फिर जुदाई का दर्द यहां सबके लिए एक अलग नज्म है। आज आपको रीना रॉय के ही एक ऐसे बेहद चुलबुले गाने के बारे में बताएंगे जिसमें उन्होंने नाच नाचकर शत्रुघ्न सिन्हा से मीठी शिकायत की है। इसमें एक प्रेमिका का मीठा गुस्सा और नखरा दिखाया गया है।

शत्रुघ्न सिन्हा ने निभाया था डबल रोल

हम बात कर रहे हैं साल 1976 में आई सुपरहिट फिल्म कालीचरण के हिट गाने जा रे जा ओ हरजाई की। इस गाने को रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा पर फिल्माया गया है। लता जी की आवाज में ये गाना सीधा दिल में उतरता है। इस जादुई आवाज का कोई मुकाबला नहीं है। कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा ने डबल रोल निभाया है। एक में वो ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर प्रभाकर बने हैं जबकि दूसरा रोल एक कैदी का है। गाने के बोल हरजाई, देखी तेरी दिलदारी में एक प्रेमिका की शरारत साफ झलकती है। ये एक पॉपुलर डांस नंबर भी है जिसमें रीना रॉय के एक्सप्रेशन की खूब तारीफ हुई। शायद इसी वजह से उन्हें क्वीन ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता था।

इसी गाने से शुरू हुई थी प्रेम कहानी

कहा जाता है कि इसी फिल्म और इस गाने की शूटिंग के दौरान ही शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के बीच गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई थी,जो आगे चलकर बॉलीवुड के सबसे चर्चित किस्सों में से एक बनी।

विजय ने जना नायकन लीक पर क्यों नहीं दी प्रतिक्रिया? डायरेक्टर ने किया खुलासा

जना नायकन की रिलीज़ से पहले,डायरेक्टर एच. विनोथ ने बताया कि एक्टर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने थिएटर में रिलीज़ होने से कई महीने पहले फिल्म के लीक होने पर सार्वजनिक रूप से कुछ क्यों नहीं कहा। फिल्ममेकर के मुताबिक, एक्टर-राजनेता की किसी भी अपील से स्थिति सुधरने के बजाय बेवजह राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता था। मंगलवार (21 जुलाई) को चेन्नई में फिल्म के आखिरी प्रमोशन इवेंट के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए,विनोथ से पूछा गया कि जब फिल्म का हाई-डेफिनिशन वर्शन ऑनलाइन सामने आया, तो विजय ने फैंस से इसे न देखने की अपील क्यों नहीं की। वजह बताते हुए डायरेक्टर ने कहा,अगर विजय अपील करते, तो कहा जा सकता था कि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं,जिनमें किसानों का मुद्दा भी शामिल है। जब उन्होंने ऐसे मामलों पर अपील नहीं की,तो अब क्यों कर रहे हैं? इससे उनकी आलोचना हो सकती थी। विनोथ ने आगे कहा कि लीक का मामला कानूनी था और प्रोड्यूसर की शिकायत के बाद अधिकारियों ने इसे संभाला। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि विजय सर ने खुद को इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि इससे मामला भटक सकता था और आलोचना हो सकती थी। एच. विनोथ ने राजनीतिक साजिश के दावों को खारिज किया डायरेक्टर ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले विजय को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए लीक की साजिश रची गई थी।

अस्पताल में भर्ती होने की खबरों पर बोले बिग बी,पोस्ट मेसी से जुड़ी थी

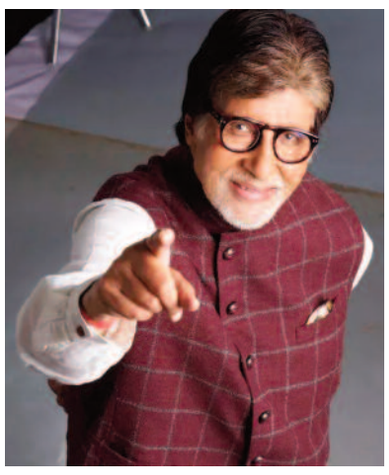

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने साफ़ किया है कि उनके हालिया ब्लॉग पोस्ट को, जिसने उनकी सेहत को लेकर काफ़ी चिंता पैदा कर दी थी,गलत समझा गया और उसका मकसद कभी भी खुद के बारे में बात करना नहीं था। दिग्गज एक्टर ने बताया कि यह पोस्ट असल में अर्जेंटीना की हार के बाद फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी से प्रेरित एक उदाहरण था। अपने ब्लॉग पर अमिताभ ने लिखा, ÷मैं ठीक हूँ... पोस्ट को गलत समझा गया...मैं एक उदाहरण दे रहा था... कि सर्जरी या ट्रॉमा में रहने के बाद का समय सबसे मुश्किल होता है, जब आप घर आते हैं...और अपनी खराब हालत का सामना करते हैं...उन्होंने आगे कहा, तो...जब कोई चैंपियन हारता है,तो उसके बाद खुद को संभालना सबसे मुश्किल होता है...अर्जेंटीना की हार और हारने वाले चैंपियन मेसी का उदाहरण...लोगों ने मान लिया कि यह मेरे बारे में है...गलत माना...हर चैंपियन को पता होना चाहिए कि समय के साथ कोई और चैंपियन भी बनेगा! उन्होंने कहा,किसी चैंपियन के लिए यह मानना मुश्किल होता है कि किसी और ने उसकी जगह ले ली है...लेकिन ज़िंदगी ऐसी ही है, यह हमेशा चलती रहती है...आप अस्पताल जाते हैं,भगवान न करे,किसी ऐसी बीमारी के इलाज के लिए जिसे ठीक करने की ज़रूरत हो...जब आप गए थे तो आपका शरीर ठीक था...लेकिन सर्जरी या इलाज के बाद,बीमारी तो ठीक हो जाती है,लेकिन उसके बाद शरीर को संभालना मुश्किल होता है...जिस तरह शरीर पहले काम करता था,शायद उसमें बदलाव आ गया हो...और उसे स्वीकार करना मुश्किल होता है...शरीर कमाल का होता है, यह ढल जाता है, काम करता है,लेकिन शायद पहले जैसा नहीं...हारने वाले चैंपियन को भी ऐसी ही भावनाओं का सामना करना पड़ता है...लेकिन...वे डटकर मुकाबला करते हैं...जब शरीर पर काम किया जाता है तो नतीजे मिलते हैं,शायद पहले जैसे न हों, लेकिन नतीजे ज़रूर मिलते हैं...चैंपियन अपनी हार से उबर सकता है, फिर से चैंपियन बनने के लिए लड़ सकता है...ज़िंदगी में सीखने के लिए अनगिनत सबक हैं...प्यार,सम्मान और भी बहुत कुछ...

खेल समाचार

इंडिया जिम्बॉब्वे मैच आज

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई गुरुवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा... टीम इंडिया का रिकॉर्ड इस मैदान पर अच्छा है लेकिन बल्लेबाजों के सामने चुनौती है...

नई दिल्ली,22 जुलाई 2026। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई गुरुवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मैदान पर अच्छा रिकॉर्ड रखती है,लेकिन यहां की पिच आउट ऑफ फॉर्म भारतीय बल्लेबाजी को टेस्ट करती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में युवा टीम इंडिया की असली परीक्षा होगी। आयरलैंड और इंग्लैंड से हार के बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम को एक-एक कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा।

हरारे में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड शानदार रहा है। भारत ने इस मैदान पर अब तक जिम्बाब्वे के खिलाफ 11 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं,जिनमें से 7 मुकाबलों में जीत हासिल की है,जबकि 4 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। खास बात यह है कि जुलाई 2024 के जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम ने इसी मैदान पर एक मैच 100 रन और दूसरा मुकाबला 10 विकेट से जीतकर अपनी ताकत दिखाई थी।

भारतीय बल्लेबाजों को हो सकती है परेशानी

आयरलैंड और इंग्लैंड में भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत का सामना करना पड़ा था। अतिरिक्त उछाल और पेस के आगे टीम इंडिया बेबस नजर आई थी। लगभग ऐसी ही चुनौती जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आ सकती है। ब्लेसिंग मुजरबानी और रिचर्ड एनगारवा लंबे कद के गेंदबाज हैं, जिनसे भारतीय बल्लेबाजी क्रम को खतरा हो सकता है। अभिषेक शर्मा,वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा पर खासी जिम्मेदारी होगी।

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों का स्क्वॉड

भारत :-श्रेयस अय्यर (कप्तान),वैभव सूर्यवंशी,अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप कप्तान),ईशानकिशन(विकेट कीपर),शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह,हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर,अशोक शर्मा,मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर),रवि बिश्नोई।

जिम्बाब्वे :- सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट,रयान बर्ल,बेन कुरेन, ब्रैड इवांस,क्लाइव मैडेंडे (विकेटकीपर), टिनोटेंडा मापोसा,तादिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा,ताशिंगा मुसेकिवा,ब्लेसिंग मुजाराबानी,डायोन मायर्स,रिचर्ड नगारवा,न्यूमैन न्यामुरी, मिल्टन शुंबा।

चाइना ओपन : सिंधु ने उन्नति को हराया

चांगझू,22 जुलाई 2026। पी.वी. सिंधु ने अपनी जीत का सिलसिला चीन ओपन में भी जारी रखा। उन्होंने पहले राउंड में साथी भारतीय उन्नति हुड्डा को कड़े मुकाबले में हराया। वहीं,बुधवार को आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए इंडोनेशिया के वर्ल्ड नंबर 11 खिलाड़ी अल्वी फरहान को हराकर पुरुष सिंगल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जापान ओपन में जीत के साथ अपना खिताब का सूखा खत्म करने के कुछ ही दिनों बाद,सिंधु ने 18 साल की हुड्डा की कड़ी चुनौती का सामना किया और 56 मिनट तक चले मुकाबले में 21-14, 9-21, 21-10 से जीत हासिल की। इस जीत ने दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु के लिए एक पुराना हिसाब भी बराबर कर दिया, क्योंकि पिछले साल इसी टूर्नामेंट में हुड्डा ने उन्हें हरा दिया था। इस बार अनुभवी भारतीय खिलाड़ी ने सुनिश्चित किया कि इतिहास न दोहराया जाए; दूसरा गेम हारने के बाद उन्होंने शानदार वापसी की। सिंधु का अगला मुकाबला दूसरे राउंड में चीन की चौथी वरीयता प्राप्त और पूर्व ओलंपिक चैंपियन चेन युफेई से होगा। पिछले हफ्ते जापान ओपन में खिताब जीतने के दौरान चीनी स्टार को हराने के बाद भारतीय खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में उतरेंगी। आयुष शेट्टी के लिए भी यह दिन यादगार रहा। उन्होंने पूर्व वर्ल्ड जूनियर चैंपियन अल्वी फरहान को 21-17, 5-21, 21-17 से हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की की। यह युवा भारतीय खिलाड़ी के लिए बदला लेने जैसा था,क्योंकि 2023 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में उन्हें इसी इंडोनेशियाई खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा था। अनुशासित और आक्रामक खेल के साथ पहला गेम जीतने के बाद, शेट्टी दबाव में आ गए क्योंकि फरहान ने दूसरे गेम में दबदबा बनाया। हालांकि, भारतीय खिलाड़ी ने निर्णायक गेम में शानदार वापसी की और आखिरी पलों में संयमित खेल दिखाते हुए अपने सीनियर करियर की सबसे यादगार जीतों में से एक हासिल की। हालांकि, डबल्स इवेंट्स में भारत के लिए दिन निराशाजनक रहा। मिक्स्ड डबल्स जोड़ी रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे को शीर्ष वरीयता प्राप्त यान झे फेंग और डोंग पिंग हुआंग से सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा,जबकि ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो भी चीन के शिन वा गुओ और फांग हुई चेन से हारकर बाहर हो गए। पुरुष डबल्स में, एम.आर. अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुनन को चौथी वरीयता प्राप्त वेई केंग लियांग और चांग वांग ने हरा दिया, जिससे इस इवेंट में भारत की चुनौती खत्म हो गई। दिन में बाद में,लक्ष्य सेन जापान के युशी तनाका के खिलाफ पुरुष सिंगल्स में अपना अभियान शुरू करेंगे।

भारत के दिग्गज एथलीट सीडब्ल्यूजी 2026 में रचने उतरेंगे इतिहास

ग्लासगो,22 जुलाई 2026। भारत 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में अनुभवी चैंपियन और उभरते हुए सितारों के साथ उतरेगा, क्योंकि देश का लक्ष्य ग्लोबल स्टेज पर एक और सफल अभियान चलाना है। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होने वाले इन गेम्स में 126 सदस्यों वाली भारतीय टीम 10 खेलों में हिस्सा लेगी। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के ओरिजिनल होस्ट के तौर पर हटने के बाद इवेंट के प्रोग्राम को 19 डिसिप्लिन से घटाकर 10 कर दिया गया था। ग्लासगो ने इस इवेंट को होस्ट करने की ज़िम्मेदारी ली है, जो 2030 में अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले भारत के लिए एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है।

भारत की मेडल की उम्मीदों में सबसे आगे ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा हैं,जो पुरुषों के जैवलिन थ्रो में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट और भारत के सबसे महान एथलीटों में से एक, नीरज एक बार फिर देश की उम्मीदों का भार उठाएंगे और अपने शानदार करियर में एक और कॉमनवेल्थ गेम्स का खिताब जोड़ने की कोशिश करेंगे। उनके साथ भारत के सबसे मजबूत मेडल दावेदारों में

वेटलिफ्टिंग की स्टार मीराबाई चानू भी शामिल हैं,जो गोल्ड कोस्ट 2018 और बर्मिंघम 2022 में जीत के बाद लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीतने की कोशिश करेंगी। पहले ही दो बार गोल्ड मेडल और एक बार ओलंपिक सिल्वर मेडल जीत चुकीं चानू, इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक बनी हुई हैं। बॉक्सिंग भी मेडल की उम्मीदों का एक बड़ा ज़रिया होगी,जिसमें लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किग्रा कैटेगरी में भारत की चुनौती की अगुवाई करेंगी। टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट और 2023 की वर्ल्ड चैंपियन लवलीना ने लगातार टॉप लेवल पर अच्छा प्रदर्शन किया है और वह अपने बढ़ते हुए अवॉर्ड्स के कलेक्शन में कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल भी शामिल करने के लिए उत्सुक होंगी। उनका अनुभव और शांत स्वभाव उन्हें ग्लासगो में भारत के प्रमुख दावेदारों में से एक बनाता है। भारत की एथलेटिक्स टीम में देश के सबसे तेज़ी से उभरते सितारों में से एक, गुरिंदरवीर सिंह भी शामिल होंगे। इस साल की शुरुआत में, इस स्प्रिंटर ने फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी करके रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया और 10.10 सेकंड की बाधा को तोड़ने वाले पहले भारतीय बने। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर गुरिंदरवीर अपने शानदार सफर को जारी रखने और कॉमनवेल्थ के बेहतरीन स्प्रिंटर्स को चुनौती देने की कोशिश करेंगे। आर्टिस्टिक जिम्नास्ट प्रणति नायक कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला मेडल जीतने की उम्मीद के साथ जिम्नास्टिक्स में भारत की चुनौती की अगुवाई करेंगी।

C M Y K

साय कैबिनेट का बड़ा फैसला : तृतीय श्रेणी पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण

खाद की सुचारू आपूर्ति के लिए बनेगी मंत्री-मंडलीय उप समिति

रायपुर,22 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद् की बैठक में राज्य की तृतीय श्रेणी पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा किसानों को खरीफ एवं रबी मौसम में उर्वरकों की समयबद्ध एवं सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

इस उप समिति में उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्री, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग,कैबिनेट मंत्री,सहकारिता विभाग एवं कैबिनेट मंत्री, वित्त विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त उप समिति के संयोजक होंगे। उप समिति आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों,विषय विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी तथा उर्वरकों की उपलब्धता एवं आपूर्ति से संबंधित विषयों पर राज्य शासन को सुझाव देगी।

मंत्रिपरिषद् की बैठक में अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास एवं सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद् ने राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों-पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा,जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। इस निर्णय से अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनके अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा।

राज्यपाल से प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों ने की सौजन्य मुलाकात

सेवा भाव,संवेदनशीलता और तार्किक निर्णय से निभाएं दायित्व : रमेन डेका

रायपुर,22 जुलाई 2026। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक पद नहीं, बल्कि आम जनता की सेवा का महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर का पूरी निष्ठा,संवेदनशीलता और ईमानदारी से निर्वहन करना प्रत्येक अधिकारी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि जहां चुनौतियां होती हैं, वहीं नए अवसर भी मौजूद होते हैं। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति का सकारात्मक दृष्टिकोण से सामना करते हुए जनता के हित में निर्णय लिए जाने चाहिए। राज्यपाल आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वर्ष 2025 बैच के प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों से चर्चा कर रहे थे। ये अधिकारी वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी, निमोरा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों ने अकादमी के महानिदेशक टी.सी. महावर के नेतृत्व में राज्यपाल से सौजन्य भेंट की। राज्यपाल ने कहा कि प्रशासनिक निर्णय में मानवीय संवेदनाओं का भी समावेश होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक कार्य में ह्यूमन टच होना आवश्यक है,ताकि शासन की योजनाओं और निर्णयों का लाभ वास्तविक रूप से आम नागरिकों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनता से नियमित संवाद करना चाहिए,क्षेत्र का सतत भ्रमण करना चाहिए और लोगों की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कार्य संभव हो, उसे प्राथमिकता के साथ पूरा करें और यदि किसी कारणवश कोई कार्य संभव नहीं है तो उसकी स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी संबंधित व्यक्ति को अवश्य दें। इससे प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होता है। राज्यपाल ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए तार्किक सोच और विवेकपूर्ण निष्कर्ष अत्यंत आवश्यक हैं। तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेना ही एक सक्षम अधिकारी की पहचान है। उन्होंने कहा कि जनता को न्याय दिलाना लोक सेवक का प्रथम कर्तव्य है और प्रत्येक अधिकारी को इस भावना के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे युवा हैं और उनके कंधों पर भविष्य के प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें अपने कार्यों के माध्यम से सुशासन, पारदर्शिता और जनविश्वास को मजबूत करना होगा। राज्यपाल ने कहा कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपको छत्तीसगढ़ जैसे शांत, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य में सेवा करने का अवसर मिला है।

रामगोपाल अग्रवाल अब आबकारी घोटाले में गिरफ्तार,25 जुलाई तक ईओडब्ल्यू रिमांड मंजूर...

रायपुर,22 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में कथित आबकारी घोटाले मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने उन्हें आबकारी घोटाले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले रामगोपाल अग्रवाल को कोल लेवी घोटाले मामले में भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कोल लेवी घोटाले में मिली 14 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद रामगोपाल अग्रवाल को शुक्रवार को एसबी/ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू ने आबकारी घोटाले में पूछताछ के लिए 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईओडब्ल्यू को रामगोपाल अग्रवाल की 3 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है। अब ईओडब्ल्यू की टीम 25 जुलाई तक आबकारी घोटाले से जुड़े मामलों में उनसे पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी का कहना है कि आबकारी घोटाले से जुड़े कई पहलुओं और कथित लेनदेन की जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ जरूरी है। वहीं, इस मामले में आगे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। रामगोपाल अग्रवाल लंबे समय तक कांग्रेस संगठन से जुड़े रहे हैं और पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। कोल लेवी और आबकारी घोटाले की जांच के दौरान ईओडब्ल्यू लगातार कई लोगों से पूछताछ कर रही है। अब आबकारी घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

रायपुर में भाजपा-कांग्रेस का टकराव...पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस

कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाया,राहुल गांधी के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन

रायपुर,22 जुलाई 2026। दिल्ली में राहुल गांधी के पीएम आवास घेराव के विरोध में छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस नेता आमने-सामने हो गए हैं। भाजपा नेता कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने निकले। इस दौरान राजीव भवन के पास कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए, जिससे दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और दो बार आंसू गैस छोड़ी गई। कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने की कोशिश की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अराजकता फैलाने की कोशिश की। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी देश में अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। वहीं,कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक मामले के लिए भाजपा जिम्मेदार है। संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी की गई। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर नहीं,बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस छोड़ी गई।

आंसू गैस के असर से मची अफरा-तफरी

प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और 5 बार आंसू गैस के गोले छोड़े। आंसू गैस के असर से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कई कार्यकर्ता व पुलिस जवान इसकी चपेट में आ गए। प्रदर्शन के दौरान छोड़ी गई आंसू गैस के असर से पुलिस जवानों के साथ कवरेज करने पहुंचे रिपोर्टर भी प्रभावित हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आंसू गैस भाजपा कार्यकर्ताओं पर नहीं, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर छोड़ी गई। वहीं, पार्टी ने महिला कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी का आरोप लगाते हुए पुलिस पर पक्षपात करने का भी दावा किया।

घेराव के दौरान लगा लंबा जाम

भाजपा के घेराव प्रदर्शन के चलते शंकर नगर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रहा। बैरिकेडिंग और प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी के कारण सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने प्रदर्शन खत्म होने के बाद बैरिकेडिंग हटाकर यातायात सामान्य की गई।

प्रदर्शन के दौरान एसआई समेत 16 पुलिसकर्मी घायल जवानों से मिलने अस्पताल पहुंचे पुलिस कमिश्नर

राजधानी रायपुर में भाजपा के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन घेराव के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान एक सब-इंस्पेक्टर सहित करीब 16 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई जवानों के सिर, हाथ और पैरों में चोटें आई हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही रायपुर के पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला रामकृष्णा केयर अस्पताल पहुंचे और भर्ती पुलिस जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से घायल जवानों के स्वास्थ्य एवं उपचार की विस्तृत जानकारी ली तथा सभी घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए।

उन्होंने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। घायल जवान कलेश्वर वर्मा ने बताया कि बैरिकेटिंग के दौरान भीड़ के बीच फंस जाने से उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया। वहीं प्रशिक्षु उप निरीक्षक (पीएसआई) देवराज सिंह के सिर पर बोतल लगने से गंभीर चोट आई है, जिनका उपचार चिकित्सकों की निगरानी में जारी है। अन्य घायल आरक्षकों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस दौरान पुलिस उपायुक्त (मध्य) तारकेश्वर पटेल, एसीपी नीलेश द्विवेदी, टीआई राजेश मरई सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में 6,967 मौतें...

हाईकोर्ट ने लगाई फटकार,10 दिन में मांगा जवाब

रायपुर,22 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में बेकाबू होते सड़क हादसों और लगातार गंवाती जिंदगियों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य में एक साल के भीतर 6 हजार 967 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौत पर गंभीर चिंता जताई है। बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट परिसर में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित प्रशासनिक विभागों को शपथ पत्र के साथ 10 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हाईकोर्ट में कोर्ट कमिश्नर द्वारा पेश किए गए आधिकारिक आंकड़े प्रदेश की सड़कों की भयावह तस्वीर बयां करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के दौरान राज्य भर में कुल 15 हजार 484 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 6 हजार 967 बेकसूर लोगों की जान चली गई और 13 हजार 156 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। चिंता की बात यह

है कि साल 2026 की शुरुआत से लेकर 31 मई तक के शुरुआती पांच महीनों में ही 6 हजार 891 हादसे हो चुके हैं, जिनमें 3 हजार 170 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि यदि तत्काल कड़े कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भी विकराल रूप ले सकती है।

अफसरों की अनदेखी और कागजों में सिमटी सड़क सुरक्षा समितियां : अदालत की इस सख्ती के पीछे जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की भारी अनदेखी मुख्य वजह बनकर सामने आई है। नियमों के अनुसार हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में हर महीने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होना अनिवार्य है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। कोर्ट कमिश्नर ने बेंच को बताया कि सरगुजा जिले में साल 2025 के दौरान सड़क हादसों में 300 से अधिक मौतें हुईं, फिर भी पूरे साल में महज एक बैठक आयोजित की गई। कांकेर जिले का हाल भी ऐसा ही रहा,जहां सालभर में सिर्फ एक बार समिति की औपचारिक बैठक बुलाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि जमीनी स्तर पर हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई जा रही है।

चीफ जस्टिस ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने हाईवे पर बैठे आवारा मवेशियों और सरेराह खड़ी भारी गाड़ियों को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसे चल रही है। अदालत ने पाया कि औद्योगिक क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 10 टन की क्षमता वाले वाहनों में 22 से 25 टन तक माल लादा जा रहा है और वजन जांचने वाली वेइंग मशीनें लंबे समय से बंद पड़ी हैं। इसके अलावा सड़कों पर ट्रकों की अवैध पार्किंग भी लगातार जानलेवा हादसों को न्योता दे रही है।

रायपुर जिला बना सबसे बड़ा 'डेथ जोन'

अदालत में प्रस्तुत प्रदेश के 10 सबसे खतरनाक 'ब्लैक स्पॉट्स' (अत्यधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र) की सूची ने राजधानी रायपुर की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कुल 10 में से 7 ब्लैक स्पॉट्स अकेले रायपुर जिले में चिन्हित किए गए हैं। इनमें धरसींवा के सिलतरा से निको गेट का मार्ग बेहद खूनी साबित हुआ है, जहां एक साल में 19 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कोरबा जिले के पाली से गझरा नाला मार्ग पर 22 हादसों में 17 लोगों की मौत दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त रायपुर के तेलीबांधा, नेवरा, आरंग और खरोरा क्षेत्र भी अत्यधिक संवेदनशील दुर्घटना क्षेत्र के रूप में सामने आए हैं।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

रायपुर,22 जुलाई 2026। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कथित शराब घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को मिली जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि,कोर्ट ने जांच एजेंसी के खिलाफ हाईकोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों को अनावश्यक बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया।

यह मामला कथित तौर पर 2,161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़ा है। बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत,जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मामले में सुनवाई की। बेंच ने कहा कि इस मामले से जुड़े कानूनी मुद्दे कोर्ट के सामने अभी भी खुले रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के आदेशों को रद्द करने के बारे में जरूरी कानूनी सवाल भी उठाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या सिर्फ इसलिए जमानत के आदेश रद्द कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि उनमें पर्याप्त कारण नहीं बताए गए हैं। बेंच ने आपराधिक

मुकदमों को पूरा करने पर ध्यान देने के बजाय जमानत के आदेशों को चुनौती देने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई। बघेल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने जमानत रद्द करने की बढ़ती कार्यवाही का जिक्र करते हुए इस बात से सहमति जताई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी माना कि कानूनी रूप से गलत जमानत आदेश जरूरी नहीं कि किसी आरोपी की आजादी को रद्द करने को सही ठहराए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने की याचिका खारिज करने का फैसला किया। इसी बीच, सीनियर एडवोकेट जेठमलानी ने कहा कि हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी के खिलाफ गैर-जरूरी सख्त टिप्पणियां की थीं। कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से जांच एजेंसी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को यह कहकर हटा दिया कि यह टिप्पणियां पूरी तरीके से अनावश्यक थी। हाईकोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में चुनिंदा गिरफ्तारियां करने और 'पिक एंड चूज' का तरीका अपनाने के लिए राज्य की आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की आलोचना की थी। दरअसल, कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामलों में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को जनवरी में जमानत दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ईडी और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका में दलील दी गई कि चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद से मामले का कोई भी मुख्य गवाह सामने आने से डर रहा है। सीबीआई और ईडी दोनों इस मामले में जांच कर रही हैं। ईडी का दावा है कि इस तथाकथित घोटाले में 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने से भारी गड़बड़ी की गई।

बीजेपीके कांग्रेस दफ्तर घेराव पर दीपक बैज ने कहा-यह प्रदर्शन नहीं हमला था..लाठी, डंडे और पत्थर लेकर पहुंचे थे भाजपाई

रायपुर,22 जुलाई 2026। बीजेपी के कांग्रेस कार्यालय घेराव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में हुई घटना के विरोध में राहुल गांधी के प्रदर्शन से बौखलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। बैज ने इस घटना को प्रदर्शन नहीं बल्कि कांग्रेस कार्यालय पर हमला और आक्रमण करार दिया। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में लाठी,डंडे और पत्थर लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके गए। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी के प्रदर्शन में छह-छह मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रियों की जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने की होती है, लेकिन वे खुद ही उकसाऊ भाषण दे रहे

थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैज ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पूरी घटना के दौरान पुलिस मूकदर्शक बनी रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। बीजेपी का यह प्रदर्शन नहीं था, बल्कि कांग्रेस कार्यालय पर हमला था। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है।

अतिथि व्याख्याताओं के लिए नई नीति लागू : 11 माह सेवा और 2000 प्रतिदिन मानदेय का प्रावधान,पीरियड आधारित व्यवस्था खत्म,11 वैतनिक अवकाश भी मिलेंगे...

रायपुर,22 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने अतिथि व्याख्याता नीति-2026 लागू कर दी है। नई नीति के तहत पीरियड आधारित व्यवस्था समाप्त कर 2000 प्रतिदिन मानदेय,11 माह की सेवा और 11 वैतनिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। नई व्यवस्था से उन महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को विशेष लाभ मिलने की संभावना है,जहां अब तक उन्हें प्रतिमाह लगभग 20 हजार से 25 हजार तक मानदेय मिलता था। नई नीति लागू होने के बाद उनका मासिक मानदेय बढ़कर लगभग 40 हजार से 42 हजार तक पहुंच सकता है।

सेवा की निरंतरता पर जोर : नई नीति में सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। पहले कई महाविद्यालयों में दिसंबर और जनवरी के सेमेस्टर परीक्षा अवधि के दौरान अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं समाप्त कर दी जाती थीं, जिससे उन्हें आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता था। अब 11 माह की सेवा मिलने से इस समस्या के समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। संशोधित व्यवस्था के तहत अतिथि व्याख्याताओं की श्रेणी दैनिक वेतनभोगी के रूप में भी निर्धारित की गई है।

समस्याओं के समाधान का आश्वासन

उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा है कि नीति के क्रियान्वयन के दौरान यदि किसी प्रकार की व्यावहारिक समस्या सामने आती है तो विभाग स्तर पर उसका समाधान किया जाएगा। नई नीति लागू होने के बाद प्रदेशभर के अतिथि व्याख्याताओं ने इसका स्वागत किया है। शासकीय मूल निवास अतिथि व्याख्याता कल्याण संघ,छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लव कुमार वर्मा, प्रदेश सचिव डॉ. कमलेश देशमुख, बिलासपुर संभाग अध्यक्ष आलोक चतुर्वेदी सहित पदाधिकारियों ने इसे आर्थिक सुरक्षा और सेवा की स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)